नई समाजवादी क्रान्ति का उद्घोषक

बिगुल

मासिक समाचार पत्र • वर्ष 3 अंक 10
नवम्बर 2001 • तीन रुपये • बारह पृष्ठ

आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो)

आतंकवाद बहाना है जनता ही निशाना है

सरकार की नज़र में देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा देश की जनता से सरकार ने ठान लिया है कि विरोध की हर आवाज का गला घोंट दो

(विशेष संवाददाता)

आतंकवाद की आड़ में केन्द्र सरकार ने अब तक का सबसे जनविरोधी काला कानून आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) जारी कर दिया है। पिछले 24 अक्टूबर को जारी इस अध्यादेश के प्रावधान इतने खतरनाक हैं कि इसके आगे वह रौलेक्ट ऐक्ट भी बेहद हल्का-फुल्का कानून लगेगा जिसका विरोध कर रहे लोगों को अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग में भून डाला था। संविधान के पोथे में लिखी नागरिक आज़ादी और जनतांत्रिक अधिकारों का मोल मेहनतकश जनता के लिए तो कागज पर उभरी काली आकृतियों से अधिक कुछ नहीं था। यह अध्यादेश अगर संसद में पास होकर कानून बन गया तो इन इबारतों पर अब पूरी तरह काली स्याही पुत जायेगी।

पोटो के प्रावधानों के तहत अब सरकार की नीतियों के विरोध की कोई भी हिंसक-अहिंसक कार्रवाई को आतंकवादी कार्रवाई का नाम दिया जा सकता है। यानी आतंकवाद को कुचलने के नाम पर इस कानून में सत्ता के किसी भी किस्म के विरोध का गला घोंटने और आम जनता पर सरकारी आतंक थोपने के पक्के इंतजाम कर दिये गये हैं।

जिस तरह से आपातकाल के दौरान आन्तरिक सुरक्षा पर खतरे से निपटने के नाम पर कुख्यात आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), आगे चलकर 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' (रासुका) और आतंकवाद को दबाने के नाम पर 'आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक अधिनियम' (टाडा) लागू किया गया है, ठीक उसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने पोटो जारी कर दिया गया है। ग्यारह सितम्बर को न्यूयार्क-वाशिंगटन पर आतंकवादी हमलों के बाद पैदा हुई स्थिति ने सरकार को यह अध्यादेश जारी करने का एक बेहद माकूल मौका भी मुहैय्या करा दिया है।

पोटो के प्रावधानों के तहत ऐसी किसी भी कार्रवाई को आतंकवाद मान लिया जायेगा जिसके पीछे भारत की एकता-अखण्डता, सुरक्षा या सम्प्रभुता को चोट पहुंचाने की मंशा हो। पोटो की धारा 3 (1) (a) कहती है कि ". .. किसी की हत्या करने, अपंग बनाने, चोट पहुंचाने, सम्पत्ति नष्ट करने या आवश्यक सेवाओं को बाधित करने की मंशा से किया गया कार्य आतंकवादी कार्रवाई मानी जायेगी।" इसी धारा के तहत आगे यह भी लिखा है कि इस "आतंकवादी कार्रवाई" को अंजाम देने के लिए बम, डायनामाइट, विस्फोटक सामग्रियां, आग्नेयास्त्र, विनाशकारी

(पेज 10 पर जारी)

यदि जनता की बात करोगे,
तुम गद्दार कहाओगे
बम्ब सम्ब की छोड़ो,
भाषण दिये तो पकड़े जाओगे
निकला है क़ानून नया,
चुटकी बजते बंधा जाओगे
न्याय, अदालत की मत पूछो,
सीधे मुक्ति पाओगे

– शंकर शैलेन्द्र, 1948

काबुल पर नार्दन एलाएंस का कब्जा, तालिबान पीछे हटे

लेकिन अमेरिकी मंसूबों की कामयाबी आसान नहीं

(बिगुल प्रतिनिधि)

दिल्ली। काबुल और मजार-ए- शरीफ पर नार्दन एलाएंस का कब्जा। बचे-खुचे तालिबान पीछे हटकर दक्षिणी अफ़गानिस्तान के दुर्गम पहाड़ों में चले गये हैं। अल कायदा का नेटवर्क लगभग तहस-नहस हो चुका है। ... लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी बमबारी जारी है। ... इसलिए नहीं बिन लादेन अभी "जिन्दा या मुर्दा" नहीं पकड़ा जा सका है। बल्कि इसलिए, क्योंकि हमले के पीछे छिपे अमेरिकी मंसूबे अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस मंसूबे में थोड़ी-बहुत कामयाबी तभी मिल सकती है जब काबुल में ऐसी सरकार बने जो उसकी राह का रोड़ा न बने। इसलिए अब यह कवायद भी जोरों पर है।

अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले के पीछे छिपे मंसूबे अब धीरे-धीरे उन लोगों को भी नज़र आने लगे हैं जिनकी आंखों के सामने पूंजीवादी मीडिया ने खबरों की बमबारी करके काला धुआं फैला रखा है। अमेरिकी हुक्मरानों की ललचायी नज़रें कैस्पियन सागर के विशाल अनछुए तेल के भण्डारों पर टिकी हैं। यह अमेरिकी हमलों का सबसे अहम आर्थिक पहलू है। ।। सितम्बर की घटना के बाद दुनिया के महाबली की गिरी साख को दुबारा वापस लौटाने की कोशिश, समूची दुनिया की जनता के दिलों में साम्राज्यवादी आतंक बिठाने की कोशिश, दक्षिण एशिया में फौजी दखलन्दाजी की ज़मीन तैयार करने की कोशिश आदि अमेरिकी मंसूबों के राजनीतिक और फौजी पहलू हैं। ये सभी पहलू साफ तौर पर उजागर हैं। इसके लिए सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। हत्यारे अमेरिकी हुक्मरान चाहे जितने शातिर रहे हों या हों उनके मंसूबों के अनगिनत सबूत पहले भी सामने आते रहे हैं, आज भी सामने हैं।

यूं भी आज की दुनिया में "अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मानवता की रक्षा" या "आज़ादी एवं न्याय की रक्षा के लिए अभियान" जैसी लफ्फाजियों की आड़ में साम्राज्यवादी मंसूबों को छुपाये रखना सम्भव भी

(पेज 6 पर जारी)

भीतर के पन्नों पर

1. 'संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा' का गठन -पृ. 3
2. होण्डा पावर प्रोडक्ट्स में संकट की घड़ी - पृ. 4
3. इस बरबादी का उपाय क्या है स्टिग्लिट्ज़ महोदय - पृ. 4
4. 'उदारीकरण के कोरामिन' का इंजेक्शन भी नाकामयाब - पृ. 5
5. कलकत्ता में 'अतिक्रमण हटाओ' अभियान में बर्बरता के नये कीर्तिमान - पृ. 8
6. मजदूर क्रांति ही साम्राज्यवादी युद्धों का नाश करेगी! – लेनिन -पृ. 9

विश्व व्यापार संगठन की दोहा बैठक

मेहनतक़श हों बदहाल, सरकार बजाये गाल

(बिगुल प्रतिनिधि)

दिल्ली। कतर की राजधानी दोहा में सम्पन्न विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से भारतीय प्रतिनिधिमण्डल कौन सी रियायतें लेकर लौटा है, इसके ब्यौरे के बारे में जानबूझकर सरकार जनता से छुपा रही है। प्रतिनिधिमण्डल के नेता वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन चाहे जितना गाल बजा रहे हों लेकिन इस सच को वे छुपा नहीं सकते कि विश्व व्यापार के चौधरियों के आगे सरकार ने एक बार फिर घुटने टेक दिये हैं।

घुटने टेकने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भारत डब्ल्यू.टी.ओ. के एक नये चक्र की वार्ता के लिए तैयार हो गया है। दोहा रवाना होने से पहले इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आग उगलने वाले भाषण झाड़े जा रहे थे कि जब तक पहले तय हुए मुद्दों के अमल की समीक्षा नहीं हो जाती तब तक नये चक्र की वार्ता के लिए भारत कतई राजी नहीं होगा। सम्मेलन के शुरुआती दिनों में ऐसी खबरें आ रही थीं कि भारतीय प्रतिनिधि अड़े हुए हैं और अमेरिकी, जापानी एवं यूरोपीय प्रतिनिधि मनाने-चुनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सम्मेलन खत्म होने पर जो साझा बयान जारी हुए उससे यह साफ हो गया कि उन्हें "मना लिया" गया है – यानी भारतीय प्रतिनिधियों ने सरकार की नीतियों के तहत आखिरकार घुटने टेक दिये।

सरकार जो रियायतें गिना रही है अगर वे मिली भी हैं तो इससे देश की मेहनतकश जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। एड्स, मलेरिया व कुछ अन्य महामारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं के क्षेत्र में पेटेण्ट कानून में थोड़ी रियायत मिली है। इसे ही एक ठोस रियायत कही जा सकती है। लेकिन इसका फायदा भी मिलेगा देश की दवा कम्पनियों के मालिकों को, जो इस क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुकाबले में थोड़ा टिक सकेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देश की जनता को जीवनरक्षक दवाएं सस्ती मिलने लगेंगी। इन दवाओं की कीमतों

(पेज 6 पर जारी)

बजा बिगुल मेहनतकश जाग, चिंगारी से लगेगी आग!

आपस की बात

कर्मचारी की जगह कम्प्यूटर लें और हम धीर धरें?

'बिगुल' अक्टूबर' 01 अंक में व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट के बहाने डाक विभाग पर सरकारी जकड़बन्दी की रिपोर्ट पढ़े अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता कि आज ही अखबार में लुधियाना (पंजाब) से छपी एक खबर देखने को मिली – "छोटे व घाटे वाले डाकघर बंद होंगे।"

'बिगुल' ने जिन सुझावों/प्रावधानों की आशंका प्रकट की थी, वह तो लागू भी होने लगी। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार कितनी तेज गति से कार्य कर रही है। पंजाब के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अजीत शेर इंदर सिंह पाल के हवाले से छपी उक्त खबर में बताया गया है कि देश में डाकघरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सरकार छोटे व कमाई न करने वाली शाखाओं को बंद करने जा रही है। मुख्य डाकघर कम्प्यूटराइज्ड होंगे और वहां एटमी सेवा शुरू होगी।

सी.पी.एम.जी. पाल साहब की वाणी पर गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नयी भर्ती पर रोक लगा दी है, पुराने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों की भरपाई के लिए डाकघरों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है। क्या खूब कहा है पाल साहब ने। यही तो आज के दौर की सच्चाई है।

देखिए, कितना ख़तरनाक मंजर है। एक तरफ हमें घुट्टी पिलाई जा रही है – आतंकवाद से निपटना है, सुरक्षा को खतरा है सब लोग धैर्य धरो। दूसरी तरफ, कर्मचारियों की भरपाई कम्प्यूटर से की जा रही है। आख़िर क्यों? 'बिगुल' में छपी ब्रेष्ट की कविता के ही अनुसार हम धैर्य धरें वे राज करें।

यह हम सबके सोचने का विषय है कि आखिर कब तक हम धैर्य धरें?

-धीरेन्द्र नाथ
मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ

आम जनता इस तानाशाही का जवाब देने की तैयारी न शुरू कर दे?

इतिहास गवाह है कि क़ानून ने कभी आतंकवाद को खत्म नहीं किया है। कानूनों क. तो ढेर हमारे पास है, मगर कानूनों का सही उपयोग कहां हो रहा है?

जो देश, दुनिया की सबसे अधिक आबादी रखता हो, जिस देश की निरक्षर कौम इतनी अधिक हो कि हर तीसरा, व्यक्ति अनपढ़ हो, जिस देश की आधी जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहने को लाचार हो। जिस देश में मुख्य धारा से जुड़ी महिलाओं की संख्या आज भी दो अंकों (7% से भी कम) को भी न पहुंच पा रही हो, जिस देश की जनता अनाज होते हुए भी भूखों मरने को मजबूर हो, जिस देश का अमीर वर्ग और अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब हो रहा हो, जिस देश में इमानदारी और सच्चाई महज कुछ शब्द बन कर रह गये हों, जिस देश का युवा आज भी झूठे आश्वासनों की जमीन पर सपनों का चादर ओढ़ने को मजबूर हो, उस देश में कानूनों पर कानून बनाकर आतंकवाद रोकने की कोशिश नाकाम होगी।

क्या आतंकवाद व अपराधों के मूल जड़ों में जाने की आवश्यकता है। इस. पेड़ के सिर्फ पत्ते काटने से क्या होगा? हजार पेड़ और उग आयेंगे। इन पेड़ों के जड़ों में छिपी है –बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस व सैनिकों की बर्बरता, राजनीतिज्ञों की मनमानी, विकास नीतियों का अभाव, पिछड़े वर्गों का शोषण और न जाने ऐसे कितने ही प्रश्न। इन प्रश्नों के ही उत्तर से निकलेगा आतंकवाद या अपराधों का हल।

इस देश की पुलिस और कानून को पोटो जैसे हथियार देने के बाद आम जनता कहीं इस तानाशाही का जवाब देने की तैयारी न शुरू कर दे। जिसकी कसमसाहट शुरू भी हो चुकी है।

– विशाल सराय हसनगंज, लखनऊ

सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में क्रान्ति का बिगुल बजेगा

बिगुल नियमित समय से मिल रहा है। वैसे तो बिगुल का हर अंक संग्रहणीय होता है लेकिन इस बीच 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' नाम से जो कालम आपने शुरू किया है वह आम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के बीच एक सही लाइन को समझने में मदद देगा। आजकल यह इसलिए भी जरूरी है कि आज जब 'साम्राज्यवाद एक कागजी बाघ' साबित हो रहा है, पूंजीवाद की सारी उर्जा समाप्त प्राय हो चुकी है एवं अब वह 'नरभक्षी बाघ' की तरह हिंस्र हो चुका है। बुर्जुआ संसदीय कुत्तालघसीटी भी जनता देख चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे आज के तथाकथित कम्युनिस्ट नामधारी लालझंडा वाली पार्टियों को भी यहां की जनता ने देखा है। ऐसे में हमारे सामने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभार हैं कि हम जनता के बीच मज़दूरों की पार्टी की सच्ची पहचान करायें। हम जानते हैं कि 200 सालों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 54 सालों में देशी पूंजीपतियों की गुलामी को जिस जनता ने देखा हो उसमें अभी बहुत निराशा है। उस पर से खुश्चेव, देंग, त्रात्सकी आदि के पद-चिन्हों पर चलने वाली विभिन्नता संशोधनवादी वामपंथी पार्टियों की वजह से आम जनता को एक सही लाइन को समझने में वक्त लगेगा। और जल्दी ही जनता अपनी ताकत को पहचानेगी और एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी के नेतृत्व में क्रान्ति का बिगुल फूंकेगी सच यही है कि सर्दियां उनकी है बसन्त हमारा होगा।

... न्याय के इस महाकाव्यात्मक समर में

हो पराजित सत्य चाहे बार-बार
जीत अन्तिम उसी की होगी
आज फिर यह घोषणा
करते हैं हम।

विनोद कुमार,
बलिया (उ.प्र.)

इस मुहिम में, आपके साथ

'बिगुल' लगातार मिल रहा है। यह सही बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका ही है। जो चल रहा है वह युद्ध नहीं सरासर उसकी दादागिरी है एशिया में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए। 'बिगुल' के पिछले अंक में 'कैलिफोर्निया के बिजली संकट' के माध्यम से अपने निजीकरण के भयावह दुष्टपरिणामों को बखूबी उजागर किया है।

'बिगुल' की इस मुहिम में मुझे भी साथ मानकर चलिये।

– विकास पाण्डेय रायपुर,(म.प्र.)

हरियाणा स्टील एण्ड एलॉयस के मजदूरों पर जिला प्रशासन का लाठी चार्ज

(पोटो लागू होने से पहले पिटाई शुरू)

(बिगुल संवाददाता)

सोनीपत। हरियाणा स्टील एंड एलायज प्रा. लि.क. जो जी.टी.रोड मुरथल, सोनीपत में स्थित है, मजदूरों के शोषण का अड्डा बनी हुई है। पिछले वर्षों से यहां के मज़दूर ए.आई.सी.सी.टी.यू. ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में, आर्थिक मुद्दों पर कई क़ानूनी व रोजमर्रा की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसी तरह की एक आर्थिक लड़ाई के तहत जब इस महीने कम्पनी के मजदूरों ने रिकार्ड प्रोड्क्शन (3850 टन) के लिए जब बोनस पी. एफ. और कैंटीन सुविधाओं की मांग की तो मालिक ने मजदूर वर्ग को इनाम देते हुए, पांच नेतृत्वकारी मजदूरों को सस्पेंड कर दिया। मालिक की इन्हीं कारगुजारियों के विरोध में जब यूनियन के नेतृत्व में मजदूर, डी.सी. महोदय, को ज्ञापन देने पहुंचे, तो उपायुक्त महोदय ने मालिकों का ही पक्ष लिया व नेतृत्व के साथ अभद्र व्यवहार किया। इसी सब के फलस्वरूप उपायुक्त महोदय ने पुलिस को बुलाकर, वहां उपस्थित सौ के करीब मजदूरों पर लाठी चार्ज करवाया और उन्हें आधे कि.मी. तक दौड़ा कर पीटा। नेतृत्व के दो अधिकारियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया गया।

साथियो। मालिकों और सरकारी मशीनरी(पुलिस और न्याय) के गठजोड़ का दमनचक्रों एवं लाठियों गोलियों के बल पर मजदूरों पर कहर ढाने का इतिहास रहा है। उपरोक्त घटना भी इसी का एक हिस्सा है। अत: हमें अब यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये सरकारें, कानून, पुलिस, प्रशासन हमें मालिकों के चंगुल से नहीं बचा सकते बल्कि ये तो पूंजीपतियों के पालतू कुत्ते हैं जो उन्हीं की चौकसी करेंगे। ऐसे में, साथियों! यदि हम अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, इनका मुकाबला करना चाहते हैं, और शोषण, उत्पीड़न के चंगुल से आजाद होना चाहते हैं तो हमें अपनी जुझारू एकता के हथियार पर विश्वास करना होगा और यह जुझारू एकता केवल अपनी-अपनी फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि हर संघर्ष के समय, शांति के समय में भी इलाकाई स्तर पर अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों के साथ, गांव के गरीब किसानों के साथ, छात्र-नौजवानों के साथ मजबूत एकता स्थापित करने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। तभी हम इन हथकंडों का माकूल जवाब दे सकेंगे और साथ ही अपनी मुक्ति की तरफ भी बढ़ सकेंगे।

बिगुल का स्वरूप, उद्देश्य और ज़िम्मेदारियां

1. 'बिगुल' व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मजदूरों के बीच क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा संस्कृति का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओं से, अपने देश के वर्ग संघर्षों और मजदूर आंदोलन के इतिहास और सबक से मजदूर वर्ग को परिचित करायेगा तथा तमाम पूंजीवादी अफवाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ करेगा।

2. 'बिगुल' देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक स्थितियों के सही विश्लेषण से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा।

3. 'बिगुल' भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओं के बारे में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मजदूरों की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और व्यवहार में सही लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो।

4. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के बीच लगातार राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित करायेगा, उसे आर्थिक संघर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर "कम्युनिस्टों" और पूंजीवादी पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनबाजों से आगाह करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सुधारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की कतारों से क्रान्तिकारी भरती के काम में सहयोगी बनेगा।

5. 'बिगुल' मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी संगठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी भूमिका निभायेगा।

पाठक साथियों से

'बिगुल' को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके अधिक से अधिक ग्राहक बनायें।
कारखानों, वर्कशापों, दफ़्तरों के गेट पर बिगुल बेचें।
बिगुल के लिए अधिक से अधिक चन्दा जुटाकर भेजें।
इसके लेखों पर अपने और अपने साथियों के विस्तृत विचार लिखकर भेजें जिससे हम इसे और सुधार सकें।
अपने इलाके के मज़दूरों की समस्याओं और उनके संघर्षों पर रिपोर्ट भेजें।
'बिगुल' की प्रतियों और बिगुल सहयोग कूपन के लिए हमें इस पते पर पत्र लिखिए।

सम्पादक 'बिगुल'
द्वारा ओ.पी.सिन्हा 69, बाबा का पुरवा,
पेपर मिल रोड निशातगंज, लखनऊ 226006

बिगुल यहां से प्राप्त करें

♦ शहीद पुस्तकालय, डा. दूधनाथ, जनगण होम्यो सेवा सदन, **मर्यादपुर, मऊ** ♦ मौर्या बुक स्टाल, सआदतपुरा (निकट रोडवेज), मऊनाथभंजन, **मऊ** ♦ जनचेतना, जाफरा बाजार, **गोरखपुर**
♦ विजय इन्फारमेशन सेन्टर, कचहरी बस स्टेशन, **गोरखपुर** ♦ विश्वनाथ मिश्र, नेशनल पी.जी. कालेज, **बड़हलगंज**, गोरखपुर
♦ जनचेतना, डी 68, निरालानगर **लखनऊ**
♦ जनचेतना स्टाल, काफी हाउस के पास, हजरतगंज, **लखनऊ**, (शाम 5 से 8·30) ♦ राहुल फाउण्डेशन, 69, बाबा का पुरवा, पेपरमिल रोड, निशातगंज, **लखनऊ** ♦ विमल कुमार, बुक स्टाल, निकट नीलगिरि काम्प्लेक्स, ए ब्लाक, इंदिरानगर, **लखनऊ** ♦ रामपाल सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास विकास, **रुद्रपुर** (ऊधमसिंहनगर) ♦ रवीन्द्र कुमार, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा कार्यालय, पन्तनगर ♦ प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, विश्वनाथ मंदिर गेट, बी.एच.यू. **वाराणसी** ♦ राजीव वर्मा स्टूडेण्ट एजुकेशनल सेंटर, मैनाताली (पुलिस चौकी के पास), मुगलसराय, जिला-चन्दौली ♦ राजेन्द्र प्रसाद, रेणु मेडिकल की गली, मुख्य सड़क, **रेणुकूट**, सोनभद्र ♦ सत्यम वर्मा, 81, समाचार अपार्टमेंट, मयूर विहार-एक, **दिल्ली** ♦ ललित सती, एल.आई.सी., फैज रोड शाखा, **दिल्ली** ♦ नई किरण पुस्तक भंडार, एफ-56, हरकेश नगर, ओखला, नई दिल्ली ♦ डी. के. सचान, एस.एच.- 272, शास्त्रीनगर **गाजियाबाद** ♦ सुनील कुमार सिंह, सेक्टर-12 बी, 3159, बोकारो इस्पातनगर, **बोकारो** ♦ गणपतलाल, ग्राम काजी रसूलपुर, पो.-तेघड़ा, **बेगूसराय** ♦ पीपुल्स बुक हाउस, पटना कालेज के सामने, **पटना** ♦ समकालीन प्रकाशन (प्रा.) लि. पुस्तक बिक्री केन्द्र, आज़ाद मार्केट, पीरमुहानी, **पटना** ♦ विमर्श, 22, स्वास्तिक काम्प्लेक्स, रसल चौक ,जबलपुर ♦ नरभिन्दर सिंह, द्वारा डा. सुखदेव हुन्दल, ग्रा/पो. **सन्तनगर**, जिला-सिरसा ♦ पंकज, प्लाट नं. 33, सेक्टर-15, सोनीपत (हरियाणा) ♦ सुखविंदर द्वारा कॉ0 दशरथ लाल, मकान नं 14, लेबर कॉलोनी, गिल रोड, लुधियाना (पंजाब) ♦ राकेश गोरखा, सरस्वती पुस्तक मंदिर, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी, **दार्जीलिंग** ♦ बुक मार्क, 6, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, **कलकत्ता** ♦ शर्मा बुक स्टाल, थाना रोड, चराली, **तिनसुकिया** नेपाल ♦ विश्व नेपाली पुस्तक सदन, श्रवनपथ, बुटवल, रुपनदेई, **नेपाल** ♦ विशाल पुस्तक सदन, बिजुवार बाजार, प्यूठान राप्ती अंचल ♦ विशाल पुस्तक पसल, अस्पताल लाइन, बुटवल, **लुम्बिनी**, नेपाल ♦ लक्ष्मी नारायण मिश्र, 853, हिरनमगरी, सेक्टर 4, पूजानगर, **उदयपुर** (राज.)

बिखराव के इस दौर में इलाकाई एकता के लिए एक जबर्दस्त पहल

'संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा' का गठन

बिगुल संवाददाता

रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)। एक ऐसे समय में जबकि पूरा मज़दूर आंदोलन बिखराव का शिकार है, तराई-नैनीताल क्षेत्र में मज़दूर एकता की शानदार शुरुआत करते हुए 'संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा' का गठन हुआ। मज़दूर-कर्मचारी यूनियनों-संगठनों-मंचों के इस इलाकाई साझा मोर्चे ने खण्ड-खण्ड में बिखरे मज़दूर आन्दोलन को एक सूत्र में पिरोने का संकल्प लेते हुए यह विश्वास जताया है कि 'सही उद्देश्य के लिए सही रास्ते से सच्ची लड़ाई लड़ी जाएगी तो व्यापक मेहनतकश आबादी विजयी होगी'।

आम सहमति के साझे कार्यक्रम का यह मोर्चा इलाकाई आन्दोलनों में संयुक्त कार्यवाही करने के साथ ही देश-प्रदेश के मज़दूर-कर्मचारी आन्दोलनों में समर्थन/सहयोग देने के साथ अपनी बिरादराना एकता प्रदर्शित करेगा। मोर्चा संगठित व असंगठित सभी क्षेत्र के मज़दूर आन्दोलनों को संगठित करेगा। मोर्चा, निजीकरण- छंटनी-तालाबन्दी-श्रम कानूनों में घातक परिवर्तनों व जनवादी अधिकारों के हनन जैसे मज़दूरों-कर्मचारियों पर नीतिगत हमलों का विरोध करेगा। वह राज्य से उद्योगों का पलायन रोकने के लिए संघर्ष करेगा। यह शोषण-उत्पीड़न व रोजगार सुरक्षा की गारण्टी को मुद्दा बनाएगा।

मोर्चे की प्रस्तावना में पिछले एक दशक से जारी उदारीकरण-निजीकरण-छंटनी-तालाबन्दी-विनिवेशीकरण-ठेकाकरण-श्रम कानूनों में घातक परिवर्तनों, निजी कारखानों में मज़दूरों की बढ़ती निरंकुशता उत्तरांचल राज्य से उद्योगों के पलायन से उद्योग शून्य राज्य बनने के बढ़ते ख़तरों के समानान्तर मज़दूर आन्दोलनों के लगातार पीछे खिसकते जाने की चर्चा की गयी है।

प्रस्तावना में लिखा है कि "अपने-अपने विभागों-कारखानों के स्तर पर और अपनी-अपनी सहूलियतों की लड़ाइयां लड़ते-लड़ते, अलग-अलग क्षेत्र के मज़दूर-कर्मचारी एक-दूसरे से अलग होते गये हैं। क्षेत्रवाद-जातिवाद, सरकारी क्षेत्र-निजी क्षेत्र और अलग-अलग यूनियनों के संकीर्ण बंटवारे ने आंदोलन को और ज़्यादा कमजोर बनाया है। जबकि विश्व बैंक-आई.एम.एफ.-विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक लुटेरी संस्थाएं और उनके छुटभैय्ये फिक्की-एसोचैम-सी.आई.आई जैसी देशी लुटेरी संस्थाओं का नापाक गठबंधन मज़दूरों-कर्मचारियों को डंसने के लिए ज़्यादा एक्यबद्ध और ज़्यादा आक्रामक हुआ है।" प्रस्तावना में इस कठिन चुनौतीपूर्ण दौर में साझे मोर्चे और इलाकाई एकता के प्रयासों की महत्ता को रेखांकित किया गया है।

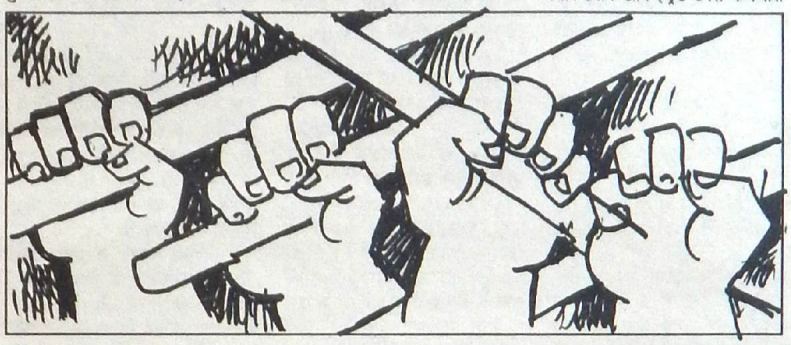

संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा में, संघर्ष के साझा कार्यक्रम पर सहमत सभी मज़दूर-कर्मचारी यूनियनों-संगठनों-मंचों के अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के तथा जिन कारखानों में यूनियनें नहीं हैं वहां के मज़दूर भी घटक सदस्य होंगे। मोर्चे की दो समितियां बनाई गई हैं – संयोजन समिति व संचालन समिति। मुख्य समिति संयोजन समिति है जो नीति निर्धारक समिति है। मोर्चे के सभी घटक सदस्य इसके सदस्य होंगे। मोर्चे के नियमित कार्यों के संचालन के लिए 'संचालन समिति' (स्टियरिंग कमेटी) बनाई गयी है। जिसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

विगत 16 सितम्बर को यहां नगर पालिका में सम्पन्न बैठक में मोर्चे का औपचारिक गठन करते हुए उसके साझा कार्यक्रम नियमावली आदि को पारित किया गया और संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति के अमर सिंह (श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन, रुद्रपुर), प्रयाग भट्ट (आनन्द निशिकावा इम्प्लाइज यूनियन, रुद्रपुर), गिरीश चन्द्र जोशी (बैंक कर्मचारी मंच, ऊधमसिंह नगर), रामपाल सिंह (बीमा कर्मचारी संघ, हल्द्वानी डिवीजन), डी. के. जोशी (चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संगठन, ऊधमसिंह नगर), मुकुल (बिगुल मज़दूर दस्ता), ए.एम.खान (पन्तनगर कर्मचारी संगठन), हरिकृष्ण भट्ट (सेंटर वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन कर्मचारी संगठन, काशीपुर) व एम.एन. उप्रेती (उत्तरांचल ऊर्जा कामगार संगठन, रुद्रपुर) सदस्य चुने गये। मोर्चे का संयोजक श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन के अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा को तथा प्रवक्ता बिगुल मज़दूर दस्ता के मुकुल को बनाया गया है। मोर्चे के वित्त ब्यूरो में गिरीश चन्द्र जोशी, रामपाल सिंह व अमर सिंह को चुना गया। इसके अतिरिक्त तीन सदस्यीय प्रेस ब्यूरो का भी गठन हुआ जिसमें मोर्चे के प्रवक्ता मुकुल के अलावा जमीर हसन खान (ट्रेड टैक्स कर्मचारी संघ, ऊधमसिंह नगर) व रवीन्द्र शर्मा (एफ.सी.आई.वर्कर्स यूनियन, रुद्रपुर) को शामिल किया गया।

बैठक के अन्त में मज़दूर विरोधी नीतियों के खिलाफ बारह सूत्री एक प्रस्ताव पारित किया गया जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, श्रममंत्री, प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निजीकरण पर रोक लगाने, श्रम कानूनों में घातक परिवर्तनों पर रोक लगाने, सरकारी/सार्वजनिक कारखानों-निगमों को बेचना रोकने, छंटनी बन्द करने व रोजगार सुरक्षा की गारण्टी देने, राज्य से उद्योग पलायन पर रोक लगाने, समान काम पर समान वेतन की पद्धति लागू करने, जनवादी अधिकारों का हनन बन्द करने, सेवानिवृत्ति की अवधि 60 वर्ष सुनिश्चित करने, मृतक आश्रितों को नौकरी सुनिश्चित करने, बन्द कारखानों/निगमों/ खाद्य गोदामों को चालू करने, श्रम न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का तत्काल निस्तारण व राज्य में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की गयी है।

मोर्चे की तरफ से किच्छा (ऊधमसिंह नगर) स्थित 'रामाविजन लि.' में श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन व प्रबंधतंत्र की अंधेरगर्दी पर तत्काल रोक लगाने और दोषी प्रबंधतंत्र को दण्डित करने की मांग करते हुए श्रमायुक्त, उत्तरांचल को एक ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि रामाविजन में दैनिक आठ घण्टे की जगह 208 घण्टे मासिक कार्यावधि निश्चित है जिसे महज 15-16 दिन के कार्यदिवस में श्रमिकों को पूरा करना होता है। शेष समय में मनमाने तौर पर कारखाना बन्द रहता है। 12-14 घण्टे की लगातार शिफ्ट ड्यूटी करने वाले यहां के श्रमिकों को अपनी जरूरत पर छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा 4 नवम्बर को सम्पन्न मोर्चे की अगली बैठक में 'लचीलेपन' के नाम पर श्रम कानूनों में प्रस्तावित घातक फेरबदल रोकने, ट्रेडयूनियन एक्ट में संशोधन को वापस लेने, ठेकाकरण को खत्म करने व मौजूदा श्रम कानूनों को सभी जगह न्यायसंगत ढंग से लागू करवाने के लिए पूरे क्षेत्र के पैमाने पर व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन को प्रधानमंत्री, श्रममंत्री, श्रम आयोग, उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल के मुख्यमंत्रियों व श्रमायुक्तों के पास भेजा जाएगा।

इसे और अधिक व्यापक बनाने की कोशिशें जारी हैं।

इस महत्वपूर्ण पहल को क्रान्तिकारी शुभकामनाएं

तराई-नैनीताल क्षेत्र में तेईस मज़दूर संगठनों-मंचों द्वारा एकजुट होकर 'संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा' का गठन करना आज के समय में एक महत्वपूर्ण जरूरी पहल है। साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के मौजूदा दौर में पूंजी की सत्ता के खिलाफ मज़दूरों के संघर्षों को धारदार बनाने के लिए अलग-अलग औद्योगिक इलाकों में बिखरी हुई मज़दूर आबादी के बीच व्यापक एकजुटता कायम करना आज के समय की जरूरत है। इसके बिना पूंजी के नग्न, बर्बर शोषण-उत्पीड़न के खिलाफ न तो फौरी मुद्दों पर ही कारगर लड़ाई लड़ी जा सकती है और न ही समूचे पूंजीवादी लूटतंत्र के खिलाफ दूरगामी लड़ाई को फैसलाकुन मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है। इस नजरिये से यह बेहिचक कहा जा सकता है कि यह पहल तराई-नैनीताल क्षेत्र के मज़दूर आंदोलन में नयी जान फूंकने वाली साबित होगी। साथ ही, यह देश भर में इस तरह की नयी-नयी शुरुआतों के लिए एक उत्प्रेरक का भी काम करेगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। यह पहल आगे बढ़े, मजबूती हासिल करे और इससे मज़दूर आंदोलन के क्रान्तिकारीकरण की कोशिशों को नयी ताकत मिले – इसके लिए 'बिगुल' की पूरी टीम की ओर से क्रान्तिकारी शुभकामनाएं!

– सम्पादक मंडल

संयुक्त मज़दूर संघर्ष मोर्चा की संयोजन समिति

1. श्रीराम होण्डा श्रमिक संगठन, रुद्रपुर
2. आनन्द निशिकावा इम्प्लाइज यूनियन, रुद्रपुर
3. बैंक कर्मचारी मंच, ऊधमसिंह नगर
4. बीमा कर्मचारी संघ, हल्द्वानी डिवीजन
5. बिगुल मज़दूर दस्ता, ऊधमसिंह नगर
6. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संगठन, ऊधमसिंह नगर
7. पन्तनगर कर्मचारी संगठन, पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर
8. उत्तरांचल राज्य कर्मचारी महासंघ, ऊधमसिंह नगर
9. एफ. सी. आई. वर्कर्स यूनियन, रुद्रपुर
10. सेंचुरी पल्प एण्ड पेपर इम्प्लाइज यूनियन, लालकुआं, नैनीताल
11. उत्तरांचल ऊर्जा कामगार संगठन, रुद्रपुर
12. उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन, मण्डल शाखा (कुमायूं)
13. हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन, ऊधमसिंह नगर
14. ट्रेड टैक्स कर्मचारी संघ, ऊधमसिंह नगर
15. सलोरा मज़दूर संगठन, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर
16. सेण्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कर्मचारी संगठन, काशीपुर
17. यू. पी. कोआपरेटिव इम्प्लाइज यूनियन, बिलासपुर, रामपुर
18. उत्तरांचल निकाय कर्मचारी संघ, ऊधमसिंह नगर
19. चीनी मिल श्रमिक संघ, गदरपुर, ऊधमसिंह नगर
20. चतुर्थ श्रेणी राजकीय कर्मचारी महासंघ, ऊधमसिंह नगर
21. मिनिस्टीरियल एसोसियेशन, सिंचाई विभाग, रुद्रपुर
22. पाली प्लैक्स इम्प्लाइज यूनियन (इण्टक), खटीमा
23. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, ऊधमसिंह नगर

इन तेईस संगठनों के अतिरिक्त पराग पशु आहार केन्द्र के लोग (जहां यूनियन नहीं है) भी इस मोर्चे में शामिल

अन्याय असमानता, शोषण-दमन के विरुद्ध विद्रोह न्यायसंगत है!

विद्रोह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।

विद्रोह करो!

विद्रोह से क्रान्ति की ओर आगे बढ़ो!

होण्डा पावर प्रोडक्ट्स में संकट की घड़ी

प्रबन्धकों के नापाक मंसूबों को पहचानो! अपने एकताबद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाओ!!

(बिगुल संवाददाता)

रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)। जनरेटर निर्माता 'होण्डा पावर प्रोडक्ट्स लि.' में प्रबंधतंत्र द्वारा कुछ विभागों का स्थानांतरण करने के जारी प्रयास से श्रमिकों में आक्रोश की स्थिति लगातार बरकरार है। प्रबंधतंत्र अपनी कारगुजारियों को अमली जामा देने के लिए सुचिंतित तरीके से कार्य कर रहा है। कारखाने के भीतर ऊहापोह की स्थिति बरकरार है।

होण्डा प्रबंधतंत्र अपनी उस मूल योजना पर कार्य कर रहा है जिसके तहत पहले ही वेल्डिंग-पेंटिंग आदि के कुछ कामों को वह बाहर ठेके पर दे चुका है। अब वह कारखाने की रीढ़ एल्युमीनियम मशीन शाप को और साथ ही स्टोर (पी सी पी सी) व पैकिंग (सी के डी/ एस पी डी) को यहां से स्थानान्तरित करने वाला है। और अन्त में रुद्रपुर का यह प्लांट होण्डा का एसिलरी बनकर रह जाएगा।

प्रबंधतंत्र 'बांटो और राज करो' के अपने पुराने फार्मूले पर काम करते हुए कारखाने के भीतर भ्रम फैलाने की योजना चला रहा है। यूनियन के भीतर विवाद पैदा करने की साजिशें जारी हैं। दूसरी तरफ विभागों की शिफ्टिंग के बावजूद मज़दूरों की नौकरी बरकरार रखने का झूठा आश्वासन भी वह दे रहा है।

बिगुल संवाददाता द्वारा कारखाने के तमाम मज़दूरों से अलग-अलग बातचीत से पता चला कि प्रबंधतंत्र के लोग मज़दूरों को अलग-अलग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन विभागों की शिफ्टिंग से उनकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। अब इनसे कोई पूछे (और तमाम कारखानों, यहां तक कि जापानी कारखानों में भी ऐसा ही हो रहा है) कि जब कारखाने का पचास-साठ प्रतिशत काम यहां से चला जाएगा तो क्या वे बैठाकर तनख्वाह देंगे, और कब तक देंगे? 'कास्ट सेविंग' की बात करने वाला प्रबंधतंत्र इतना "फालतू" व्यय कब तक वहन करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष। फिर कारखाने में घाटा दर्शाया जाएगा, फिर सबको निकाल बाहर किया जाएगा। तब मजदूर क्या करेंगे? इस एक वर्ष के दौरान संघर्ष की मंजिल भी बीत चुकी होगी।

जो स्थानीय प्रबन्धक नौकरी की गारण्टी दे रहे हैं क्या उनकी खुद की नौकरी की कोई गारण्टी है? जापानी मालिकों के वफादार स्थानीय दो शीर्षस्थ प्रबन्धकों की अभी-अभी क्या गति हुई है? एक झटके में उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया मालिकों ने। क्या मज़दूरों को प्रबंधतंत्र द्वारा वक्त पर "गारण्टी" देने और वक्त निकल जाने पर इन गारण्टियों को धता बताकर दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर करने के ढेरों उदाहरण याद नहीं हैं?

होण्डा मज़दूरों ने बातचीत के दौरान बताया कि अभी पिछले तीन-चार माह पूर्व तक सभी अस्थायी श्रमिक बाहर थे और नियमित श्रमिकों के पास भी काम नहीं था। अचानक नवम्बर माह में (आफ सीजन के बावजूद) उत्पादन सीधे दूना करके 13 हज़ार प्रति माह का उत्पादन लक्ष्य रख दिया गया और पुनः अस्थायी श्रमिकों की भर्ती कर ली गयी। जाहिरा तौर पर प्रबंधतंत्र इससे एक तीर से दो निशाने मार रहा है एक तो वह शिफ्टिंग की तैयारी के तौर पर अतिरिक्त माल स्टाक कर लेना चाहता है, ताकि बाज़ार पर कोई असर न पड़े। दूसरे, वह बनावटी उत्पादन दिखलाकर मज़दूरों में यह भ्रम पैदा करना चाहता है कि शिफ्टिंग के बाद यही अस्थायी श्रमिक निकाले जाएंगे, नियमित श्रमिकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

ध्यान देने की बात है कि जबसे कारखाने का कुछ काम ठेके पर दे दिया गया है स्थायी श्रमिकों के पास कई विभागों में काम की काफी किल्लत थी। अभी जब यह स्थिति रही है तब इन विभागों की शिफ्टिंग के बाद क्या स्थिति होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

होण्डा मज़दूरों के लिए और साथ ही कर्मचारियों के लिए भी यह अस्तित्व का संकट है। यह वक्त छोटे-छोटे आपसी विवादों में उलझने का नहीं है। यह संघर्ष करने का वक्त है। मजबूत और एकताबद्ध संकल्प बांधने का वक्त है। आज के नाजुक दौर और हालात को समझने का वक्त है।

वैसे भी होण्डा के मज़दूरों का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है। यहां के मज़दूरों के एकताबद्ध संघर्षों का ही परिणाम है कि उन्होंने तमाम सहूलियतें हासिल की हैं। पांच-छः सौ रुपये की पगार से शुरू करके इस मंजिल तक की यात्रा संघर्षों और कुर्बानियों से भरी रही हैं। साथ ही इलाकाई मज़दूरों के हर संघर्ष में शिरकत करके यहां के मज़दूरों ने हमेशा ही अपनी वर्गीय पक्षधरता निभाई है।

यह एक कड़वा सच है कि उनके लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न है। यदि वे प्रबंधतंत्र के भुलावे में आ जाते हैं तो उनके संकट का एक नया दौर शुरू हो जायेगा। विभागों की शिफ्टिंग के बाद इन पर अगला हमला तब होगा जब छह माह बाद नया वेतन समझौता उन पर थोपा जायेगा – यानी मज़दूरों द्वारा नहीं प्रबंधतंत्र द्वारा मांगपत्रक सौंपा और लागू किया जायेगा। उन्होंने तमाम संघर्षों के बाद जो सहूलियतें प्राप्त की हैं, पहले उसे छीना जायेगा। फिर छंटनी होगी और अन्त में सबको बाहर का रास्ता दिखला दिया जायेगा। यानी लोग घुट-घुट कर मरेंगे।

दूसरा रास्ता है बहादुरी का। यदि होण्डा के मज़दूर पूरे तन-मन-धन से संघर्ष करते हैं तो वे न केवल कारखाने की वर्तमान स्थिति को बहाल करवा लेंगे वरन और भी सहूलियतें पाने की मंजिल में भी पहुंच जाएंगे। आगे के संघर्षों के लिए भी मनोबल मजबूत होगा। यही नहीं, पूरे इलाके के मज़दूरों की निगाहें होण्डा मज़दूरों के संघर्ष पर टिकी हैं। संघर्षों का एक नया चेन बन जाएगा। इलाके के सभी कारखानेदारों की निगाहें भी होण्डा पर टिकी हैं और वे संघर्षों के इसी चेन से घबड़ाते रहे हैं।

होण्डा के मज़दूर स्थिति की इस नाजुकता को समझ रहे हैं और प्रबंधतंत्र के नापाक मंसूबों को भी भांप रहे हैं। इसलिए प्रबंधकों के मंसूबे ध्वस्त होंगे और मज़दूर एक बार फिर विजयी होंगे।

इस "बरबादी" का उपाय क्या है स्टिग्लिट्ज महोदय

साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण के इस दौर में जारी आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की सिर पर चढ़कर बोलती सच्चाई को पूरी दुनिया के पूंजीवादी-साम्राज्यवादी सत्ताधारी धूल-राख से चाहें जितना भी ढंकने की कोशिश करें, ढंक नहीं पा रहे हैं। झूठ के धूम्रावरण के बीच हकीकत सामने है। लाख प्रयासों के बावजूद वे मंदी से उबर नहीं पा रहे है। 'रोजगार विहीन विकास' का नारा तो वे पहले ही दे चुके हैं, बढ़ती मंहगाई पर चुप्पी साध कर वे जनता से "विकास" के लिए "कुर्बानी" की अपील करते रहे हैं। अब स्थिति वहां तक पहुंच गयी है कि पूंजीपतियों के भाड़े के कलमघसीट और उनके विद्वतजन भी सच को पूरी तरह पचा नहीं पा रहे हैं और उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है कि "आई.एम.एफ.-विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन पूरी दुनिया में एक खास प्रकार की व्यवस्था क़ायम करने में लगे धनी देशों के औजार बन गये हैं।"

इस बार अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गये तीन अर्थशास्त्रियों में से एक प्रमुख जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज वर्तमान में जारी बाज़ारवादी आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को विकासशील देशों (ग़रीब मुल्कों) की बरबादी का नुस्खा मानते हैं।

उल्लेखनीय है कि स्टिग्लिट्ज विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं और वर्तमान में वे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्रियों की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मजेदार बात ये है कि स्टिग्लिट्ज और इनके साथ नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गये दो अन्य अथशास्त्रियों जार्ज एकरलोक और माइकल स्पेंस को आर्थिक विश्लेषकों की आधुनिक (सूचना) अर्थशास्त्र विद्या की बकायदा शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। मुक्त बाज़ार की बड़ी गड़बड़ियों व विसंगतियों को दूर करने के लिए वे बाज़ारों के नियमन और उनमें सरकारों या संस्थानों के आवश्यक हस्तक्षेप की सिफारिशें करते हैं। इनका मुख्य शोध व कार्य ही इस बात पर रहा है कि कैसे पूंजी बाज़ार का सही और सटीक विस्तार हो और कैसे मुनाफाखोरों का मुनाफ़ा तेज व अबाध गति से क़ायम रहे।

पुरस्कार घोषणा के बाद स्टिग्लिट्ज अपने एक साक्षात्कार में अपनी सोच की विसंगतियां छुपा नहीं पाये और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के एक पहलू की हकीकत को उजागर कर बैठे। वे बुनियादी आर्थिक सुधार के नुस्खों में निजीकरण को रिश्वतखोरी, पूंजीवाद के उदारीकरण को अन्तरराष्ट्रीय सट्टेबाजी का विस्तार, बाज़ार नियंत्रित कीमतों की वकालत को आई.एम.एफ. का दंगा व मुक्त व्यापार को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हमला करार देते हैं।

स्टिग्लिटज कहते हैं कि विभिन्न देशों में निजीकरण के नाम पर नेताओं और अधिकारियों ने दस प्रतिशत कमीशन की लालच में अरबों की राष्ट्रीय परिसम्पत्तियां निजी हाथों में सौंप दीं। पूंजी बाज़ार को खोलने पर जब सट्टेबाजी के लिए धन देश में आ रहा हो तो शेयर बाज़ार उछाल पर होते हैं, लेकिन जैसे ही निवेश तेजी से निकलने शुरू हुए कि आई.एम.एफ. उस देश को ब्याज बढ़ाने की सलाह देता है, ताकि सट्टेबाज उस देश की पूंजी उसी देश में बनाए रखने के लिए आकर्षित हों। उनका कहना है कि बाज़ार निर्धारित कीमतों की नीति के चलते इंडोनेशिया, इक्वाडोर और बोलिविया में दंगे हो चुके हैं। मुक्त व्यापार के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दवा जैसे उत्पादों और अन्य सेवाओं की कीमतें ऊंची रखकर ग़रीब देशों की आबादी को लूटने का मौका मिलता है।

स्टिग्लिट्ज एक तरफ तो अपने शोध और प्रयोगों से बाज़ार निर्देशित अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं के बारे में विचारों में आया क्रान्तिकारी परिवर्तन मानते हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन पूंजी बाज़ार संबंधी सोच को लेकर है तो दूसरी तरफ आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की तबाही से चिंता प्रकट करते हैं। यह विसंगति पूंजीवाद की रक्षा में समर्पित महज स्टिग्लिट्ज की ही नहीं है बल्कि पूरे पूंजीवादी तंत्र की विसंगति है।

आज के दौर के – अनुत्पादक परजीवी पूंजीवादी दौर में स्टिग्लिट्ज किस आदर्श की कल्पना करते हैं, पता नहीं। लेकिन यही सच है कि मुनाफे व बाज़ार की होड़ में बड़ी पूंजी छोटी पूंजी को निगलेगी ही और बाज़ार अर्थव्यवस्था का कोई भी कार्यक्रम धनी देशों का औजार बनेगा ही। मुक्त व्यापार हो या मुनाफे की कोई भी व्यवस्था, कीमतें तो ऊंची तय ही होंगी। और कमीशनखोरी आज के दौर का स्वीकृत तरीका बन चुका है। यह भी पूंजीवादी तंत्र की ही देन है।

स्टिग्लिट्ज जैसे विद्वान चाहें जितने भी "सुधार" के नुस्खे प्रस्तुत कर लें, वित्तीय स्थिति की जानकारी के चाहें जितने भी नियम लागू कर लें, कुल मिलाकर स्थिति यही बनती है। बाजार और मुनाफे के पूरे तंत्र में बदलाव के साथ ही इस "बरबादी" का दौर खत्म हो सकेगा।

-योगेश पन्त

"सर्वहारा वर्ग केवल तभी क्रांतिकारी बन सकता है, जब वह अपने को शिल्पगत (यानी महज अपने पेशे से जुड़े हुए) स्वार्थों के संकुचित दायरे तक ही नहीं सीमित रखता है। केवल तभी वह क्रांतिकारी बनता है, जब वह सार्वजनिक जीवन के सभी मामलों और क्षेत्रों के सम्बन्ध में, समस्त श्रमजीवी तथा शोषित आम जनता के नेता के रूप में काम करता है। पूंजीपति वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जब तक सर्वाधिक कुर्बानियां देने के लिए वह तैयार नहीं होता, और वास्तव में, कुर्बानियां करता नहीं, तब तक वह अपनी सत्ता कायम नहीं कर सकता।..

खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी तथा आगे बढ़े हुए तमाम मज़दूरों को अपने-आप उठ खड़े होने वाले (स्वतःस्फूर्त) जनता के आन्दोलनों व हड़तालों को विशेष रूप से, हर प्रकार का तथा पूर्ण समर्थन देना चाहिए, क्योंकि पूंजी के जुए के नीचे, जनसमुदायों को वास्तव में जगाने, शिक्षित करने तथा संगठित करने का काम, क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास की भावना पैदा करने का काम केवल ऐसे आन्दोलन ही पूरा कर सकते हैं। इस तरह की तैयारी के बिना सर्वहारा अधिनायकत्व की स्थापना नहीं हो सकती। जर्मनी की काउत्स्की और इटली के तुराती जैसे जो लोग हड़तालों का खुल कर विरोध करते हैं, उन्हें तीसरे इण्टरनेशनल से जुड़ी पार्टियों से बेशक निकाल बाहर किया जाना चाहिए। निस्संदेह, यह चीज ट्रेड यूनियनों और संसद के उन नेताओं पर और भी अधिक मात्रा में लागू होती है, जो हड़तालों के अनुभव का इस्तेमाल करके मज़दूरों के साथ गद्दारी करते हैं, उन्हें क्रांति के बजाय सुधारवाद का पाठ पढ़ाते हैं।"

– लेनिन

(बुनियादी कामों के सम्बंध में कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की दूसरी कांग्रेस की थीसीसें, 4 जुलाई 1920)

मुनाफे की देन मंदी, मंदी से होती छंटनी, छंटनी के कारण बेकारी

उदारीकरण के "कोरामिन का इंजेक्शन" भी नाकामयाब

मुकुल

हर तरफ प्रचार का जोर है। कहीं तीन पर एक मुफ्त मिल रहा है, तो कहीं सोना बरसाने, हीरा बिखराने, लखपति-करोड़पति बनने तक के तमाम सुहाने सपने बिखेरे जा रहे हैं। 'बम्पर आफर' का दौर चल रहा है। बाज़ार तरह-तरह के सामानों से अंटा पड़ा है, लेकिन खरीदार नदारद होते जा रहे हैं। कारण – मंदी है।

भारत जैसे ग़रीब मुल्क हों अथवा जापान-अमेरिका जैसे "सर्वसम्पन्न" मुल्क, तमाम विभागों-कारखानों में बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है। कारण – मंदी है।

शेयर बाज़ार लगातार ढेर हो रहे हैं। 'इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी' और 'साफ्टवेयर' से बाज़ार को थामने के सारे प्रयास ध्वस्त होते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति लगातार गड़बड़ बनी हुई है। तरह-तरह की योजनाएं चलाकर, जनता की गाढ़ी कमाई को खींचकर, बीमा-डाक सबकी पूंजी शेयर बाज़ार में 'पूल' की जा रही है फिर भी शेयर बाज़ार में गिरावट जारी है। कारण एक ही है – मंदी।

आज पूरा पूंजीवादी तंत्र भयानक मंदी का शिकार है। इस दलदल से निकलने की वह जितनी भी कोशिशें कर रहा है, उसमें और गहरे धंसता जा रहा है। 'ढांचागत समायोजन' का रामबाण नुस्खा भी उनको संकट से उबारने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहा है। उदारीकरण के नाम पर मजदूरों-कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। आलम यह है कि हर जगह नयी भर्तियों पर रोक लग चुकी है। पुराने कर्मचारियों के 'रिटायरमेण्ट' के साथ ही वह पद भी 'रिटायर' हो जा रहा है। यानी पद को ही समाप्त कर दिया जा रहा है।

अभी पिछले दिनों पंजाब के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अजीत शेर इंदर सिंह पाल ने कहा कि "सरकार ने नए स्टाफ की भर्ती पर रोक लगाई है। पुराने कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं। कर्मचारियों की भरपाई के लिए ही डाकघरों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है।" बड़े ही मार्के की बात कही है पाल साहब ने। मुनाफाखोरों की व्यवस्था में आदमियों के पेट पर लात मारा जाएगा और उनका स्थान कम्प्यूटर ही तो लेंगे।

बहरहाल, पूरी दुनिया में आज छंटनी का जो कहर बरपा हो रहा है, जरा उस पर एक नज़र दौड़ाकर देखें।

एक जमाने में बेरोजगार विहीन "माडल" देश जापान की तमाम कम्पनियां आज बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं। मित्सुबिसी, इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन सेमी कण्डक्टर में पुनः दो हजार कर्मियों के छंटनी की घोषणा की है। अभी तीन वर्ष पूर्व इसने 15 हजार लोगों की छंटनी की थी। फुनीत्सू लिमिटेड ने 10 हजार और तोशीबा ने 17 हजार कर्मचारियों की छंटनी का फरमान जारी कर दिया है। तोशीबा जापान में कर्मचारियों की संख्या में दो प्रतिशत कटौती और करना चाहती है। यही हाल सोनी जैसी तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी है।

साम्राज्यवाद के सरगना अमेरिका में स्थिति और भी भयानक है। कम्प्यूटर और इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी (आई.टी.) से बाज़ार में उसने जो धूम मचाई थी, वह रेत का टीला ही साबित हुआ और एक झटके में भरभराकर गिर गया। अमेरिका की पर्सनल कम्प्यूटर (पी सी) कम्पनी गेटवे ने अपना एशियाई कारोबार बन्द कर दिया है और एकमुश्त 4,700 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस वर्ष के मध्य में अमेरिकी साफ्टवेयर उद्योग में अचानक आई मंदी से सारा मंजर ही बदल गया। अमेरिका के एक आउटप्लेसमेण्ट फर्म चैलेंजर, ग्रे एण्ड क्रिसमस के अनुसार (मई 01तक) कुल 51, 500 लोगों को इस संकट के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। यह प्रक्रिया लगातार जारी है और इस वर्ष के अन्त तक लगभग पचास हज़ार लोगों के बाहर हो जाने की संभावना है। इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक वहां पांच सौ बयानबे डाट कम्पनियां बंद हो चुकी हैं। अप्रैल में ही याहू डाट काम ने 12 प्रतिशत, सिस्को ने 11 प्रतिशत और लुसेन टेक ने 16 हज़ार कर्मचारियों की छंटनी कर दी थी। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अमेरिकी साफ्टवेयर उद्योग में मंदी के कारण पचास से साठ प्रतिशत लोगों को नौकरी से हाथ धोना अवश्यंभावी है।

जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कार्उंसिल के अनुसार पिछले वर्ष भारतीय रत्न व जवाहरात का निर्यात पांच फीसदी कम हो गया। वहीं देश में कम्प्यूटर की बिक्री में 14 प्रतिशत की कमी की आशंका व्यक्त की गयी है। कोरियाई देवू मोटर्स तो दिवालिया होने की मंजिल में पहुंच गयी।

मंदी के थपेड़े झेल रहे साम्राज्यवादियों के लिए 'बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा' और 11 सितम्बर को वैश्विक व्यापार के प्रतीक 'वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर' और सैन्य तंत्र के प्रतीक पेंटागन पर हमलों से उन्हें छंटनी का बम्पर मौका हाथ लगा। हमले के बाद एक सप्ताह के भीतर अमेरिकी एयरलाइंस उद्योग में 65 हज़ार लोगों को निकालने की घोषणा हो गयी। नागर विमानन उद्योग ब्रिटेन ने इससे एक कदम आगे बढ़कर निर्णय लिया और उसने 70 हज़ार कर्मियों के छंटनी की घोषणा कर दी।

डब्ल्यू. टी. सी. और पेंटागन पर हमलों के बाद मंजर यह है कि जेट विमानों की दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी बोइंग ने अपने व्यावसायिक विमान इकाई में कार्यरत 93 हज़ार कर्मियों में से सन 2002 तक 30 हज़ार छंटनी की घोषणा कर दी। युनाइटेड एयरलाइंस व अमेरिकी एयरलाइंस ने 20-20 हज़ार, कान्टीनेंटल एयरलाइंस ने 56 हज़ार कर्मियों में से 12 हज़ार व यू एस एयरवेज ने 46 हज़ार कर्मचारियों में से 11 हज़ार की छंटनी की घोषणा कर दी। डेल्टा भी घोषणा करने वाला है। ताबड़तोड़ छंटनी की इन घोषणाओं के बीच वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस ने कम से कम 12 सौ और ब्रिटिश एयरवेज ने 7 हज़ार कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है।

भारत में छंटनी का यह क्रम विगत एक दशक से जारी है और यह क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। रेलवे में 18 लाख कर्मियों की संख्या 9 लाख पर लाने की योजना है, अब तक अवकाश मुक्ति के बाद भर्ती न होने से वहां यह संख्या 13 लाख तक पहुंच चुकी है। डाक विभाग में 6 लाख कर्मचारियों की संख्या 3 लाख तक सीमित करने का प्रावधान आ चुका है। बैंकों में एक लाख सतहत्तर हजार चार सौ पांच कर्मचारी फालतू घोषित हो चुके हैं और इनमें से लगभग सवा लाख लोग बाहर हो भी चुके हैं। छंटनी के इसी क्रम में, केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए वी.आर.एस. की भी घोषणा हो चुकी है। पिछले दस वर्षों के दौरान देश में चार लाख छोटे-बड़े उद्योग बन्द हो चुके हैं और लगभग पांच करोड़ लोग सड़कों पर ढकेले जा चुके हैं। शिक्षा-चिकित्सा-रोडवेज-विद्युत-पी. डब्ल्यू.डी.-सिंचाई हर जगह छंटनी की यही स्थिति व्याप्त है।

दरअसल, बाज़ार और मुनाफे की अंधी हवस मंदी का सबसे बड़ा कारण है। लाभ और अतिलाभ का एक ऐसा भंवरजाल है जिसमें फंसा पूंजीवाद उससे निकलने की जितनी भी कोशिशें करता है, उसमें उतना ही उलझता जाता है। पहली बार 1929-32 के समय में पूंजीवाद एक बड़ी मंदी का शिकार हुआ। उस वक्त विकसित पूंजीवादी देशों – अमेरिका व यूरोपीय देशों (समाजवादी देश सोवियत संघ को छोड़कर) में उत्पादन में लगातार गिरावट और रोजगार में भारी कटौती का मंजर कायम था।

1928 से 32 के बीच अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में रोजगार में 40 प्रतिशत की कमी आयी थी। विकसित देशों में इस संकट से बेरोजगारी पहले की तुलना में और घटकर 30 से 40 प्रतिशत रह गयी। इस संकटकालीन दौर में, पहले की तुलना में अमेरिका में वास्तविक तनख्वाहों में 25 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आ गयी। इस दौर में अमेरिका में एक करोड़ पंद्रह लाख, जर्मनी में 56 लाख और ग्रेट ब्रिटेन में 23 लाख लोग बेरोजगार थे। इन देशों में 1930 में औद्योगिक उत्पादन 14.6 प्रतिशत, 1931 में 13.9 प्रतिशत व 1932 में 15.1 प्रतिशत और घटता गया। इन्हीं वर्षों में अमेरिका में कोयला उत्पादन 28 वर्ष, ढलवां लोहे का उत्पादन 36 वर्ष, इस्पात उत्पादन 31 वर्ष और कपास की खपत 11 वर्ष पीछे चला गया था।

यह मंदी पूंजीवादी समाज के सामने पहली बड़ी मंदी थी जिससे उबरने का फार्मूला पूंजीवाद के संकटमोचक कीन्स ने प्रस्तुत किया और तात्कालिक तौर पर उसे उबारा भी। हालांकि इस मंदी के ही कारण आम जनता को विश्व युद्ध की विनाशलीला को भी झेलना पड़ा था।

कीन्स का नुस्खा क्षणिक शान्ति का नुस्खा था। मुनाफा निचोड़ने का खेल जारी था फलतः मंदी का भी उबाल आता रहा। लेकिन 1972 से महामंदी (ग्रेट क्रैश) का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे पूंजीवाद एक मिनट के लिए भी छुटकारा नहीं पा सका। पूंजीवादी विश्व का वर्तमान संकट पहले से ज्यादा गहरा और ज्यादा संकटपूर्ण बन चुका है। अब यह रोग उसके लिए ढांचागत संकट बन चुका है। इस असाध्य रोग के इलाज में (आर्थिक) वैद्यराज डंकल साहब का "ढांचागत समायोजन" और उदारीकरण के कोरामिन का इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा है।

पूंजीवादी तंत्र की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह अपने मुनाफे की हवस में अति उत्पादन की मंजिल में पहुंच जाता है। उधर संतुलन बनाने के चक्कर में महंगाई बढ़ने लगती है। बाज़ार से खरीदारी घटने लगती है और मंदी का दौर शुरू हो जाता है। इस मंदी से उबरने के लिए वह छंटनी शुरू करता है। बेरोजगारी बढ़ने से लोगों की क्रयशक्ति और घट जाती है तो मंदी और बढ़ जाती है। फिर बड़े देश छोटे देश पर और बड़ी कम्पनियां छोटी कम्पनियों पर दबाव बढ़ाती हैं। छंटनी और सहूलियतों की कटौतियां और बढ़ जाती हैं। फिर तो यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जो असाध्य रोग में बदल जाता है, जैसा कि आज हो गया है।

पूंजीवाद अपने संकटों को जनता पर थोपता चला जाता है। वह मेहनतकश अवाम को बदहाल और कंगाल तो करता ही है, उसे युद्ध की आग में भी झोंक देता है। दो-दो विश्व युद्धों की तबाही जनता झेल ही चुकी है। गृह युद्ध और राष्ट्र के नाम पर छोटे युद्धों का सिलसिला तो उनके संकटों के बढ़ने-घटने के साथ तेज या धीमा होता रहता है जो बढ़ते-बढ़ते युद्धोन्माद की मंजिल में पहुंच जाता है।

आज एक बार फिर ऐसे ही संकटपूर्ण हालात कायम हो गये हैं – छंटनी-बेरोजगारी-महंगाई और इसी के समान्तर युद्ध की विनाशलीला की भयावह स्थिति कायम हो गयी है। इस स्थिति से उबरने का कोई भी रास्ता पूंजीवाद के पास नहीं है। जब तक मुनाफे और बाज़ार की व्यवस्था कायम रहेगी तब तक मंदी का, बेरोजगारी का, छंटनी-तालाबन्दी का, महंगाई का आलम व्याप्त रहेगा। एक ऐसे समाज में ही इसका समाधान सम्भव है जहां उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं के लिए हो, जहां केन्द्र में मुनाफा नहीं इंसान हो।

रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी

श्रमिक वर्ग के आर्थिक हितों पर एक और हमला

(बिगुल संवाददाता)

जबरदस्त मंदी की चपेट में फंसी भारत की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने नुकसान को लगातार मेहनतकश आबादी के मत्थे मढ़ती जा रही है। इस बेइमानी की नयी कड़ी के रूप में पिछले 22 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया तथा आरक्षित नगद अनुपात (सी.आर.आर.) को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया। सरकार लघु बचतों और पब्लिक प्राविडेन्ट फण्ड पर ब्याज दर पहले ही कम कर चुकी है।

ब्याज दरों में की गई इस कमी से सीधा फायदा पूंजीपति वर्ग को होगा और नुकसान उस मेहनतकश आबादी का होगा जो पूंजीवादी व्यवस्था की अराजकता की मार से अपने को बचाने के लिए अपना पेट काटकर अपने आय का एक हिस्सा बैंकों में रखता है। उल्लेखनीय है कि आम जनता द्वारा की गयी ये लघु बचतें ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन लघु बचतों से प्रति वर्ष लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। इसी से सरकार को अपने खर्च के लिए तथा पूंजीपतियों को अपने उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त होता है। इस कर्ज पर अब पूंजीपतियों को कम ब्याज देना पड़ेगा। यदि मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखा जाय तो पूंजीपतियों को जनता का यह पैसा लगभग मुफ्त में मिलेगा। इसके विपरीत जनता को उसके बचत के एवज में मिलने वाला पैसा लगातार कम होता जायेगा। यह जनता के मेहनत की कमाई की लूट है।

ब्याज दरों की इस कमी से आम आदमी के लिए सुरक्षित बचत का रास्ता बन्द हो गया है, क्योंकि इसमें उनकी मूल पूंजी ही लगातार कम होती जायेगी। दूसरा रास्ता है पूंजी बाजार में निवेश का, या बाजार में छोटे निवेशकों का क्या होता है इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। छोटे निवेशक का पैसा अनिवार्यतः डूबता है। तीसरा रास्ता है, वह बचत का रास्ता छोड़कर उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद में अपना पैसा खर्च करे। कुल मिलाकर सभी तरीकों में पूंजीपति वर्ग का ही फायदा है। ब्याज दरों की इस कमी के साथ रिजर्व बैंक ने आरक्षित नगद अनुपात को भी दो प्रतिशत कम कर दिया है। जनता का पैसा डूबने न पाये इसके लिए इस अनुपात को अधिक रखा जाता है। इसे कम करने का अर्थ है कि अब बैंक पूंजीपतियों को और पूंजी उपलब्ध करा पायेंगे। इस कमी से बैंकों को जनता का 7000 करोड़ रुपया और मिल जायेगा। पूंजीपतियों को देने के लिए और वह भी न्यूनतम ब्याज पर। अब यदि बैंक दिवालिया होंगे तो डूबेगा जनता का पैसा और सरकार की कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनेगी। बैंकों के दिवालिया होने की घटनायें बढ़ती ही जा रही हैं। अभी हाल में बनारस स्टेट बैंक दिवालिया हुआ है और जनता का करोड़ों रुपया डूब गया। पूंजीपतियों के अखबारों ने इसकी कोई खबर नहीं दी। बैंक का सारा पैसा पूंजीपति और सट्टेबाज खा गये। सी.आर.आर. के अनुपात को कम करना इस लूट को और तेज करेगा।

ब्याज दरों की इस कमी का सबसे बुरा प्रभाव श्रम बाजार पर पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर का श्रम भी एक माल होता है। मंदी की मार सबसे पहले श्रम पर पड़ती है। बड़ी संख्या में मजदूरों-कर्मचारियों की छंटनी होती है। पिछले पांच वर्षों में पचासों लाख मजदूर-कर्मचारी छंटनी का शिकार हुए हैं। ब्याज दरों की यह कमी श्रम शक्ति को और सस्ता बनायेगी। मजदूरों-कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, सुविधाओं में वृद्धि की जगह और कमी की जायेगी। पहले से ही न्यूनतम आय पर गुजर-बसर कर रहे मजदूरों को अब और कम मजदूरी पर काम करने को विवश होना पड़ेगा। उनकी बदहाली और बढ़ेगी।

यह पूरी अर्थ नीति ही श्रमिक वर्ग को लूटने और उसे जीवन के लिए न्यूनतम अनिवार्य संसाधनों से वंचित करने की घातक साजिश है। चुनावी पार्टियों से जुड़ी ट्रेड यूनियनें मजदूर वर्ग के श्रम-शक्ति की इस लूट का सिर्फ तमाशा देख रही हैं। और सत्ता की दलाली और हिफाजत में लगी हुई है। ऐसे में अपने हित के लिए मजदूर वर्ग को खुद पहलकदमी लेनी होगी।

रपट

जंग चाहते हैं आज जंगखोर, ताकि राज कर सकें हरामखोर

साम्राज्यवादी जंग के खिलाफ जन अभियान

(बिगुल प्रतिनिधि)

दिल्ली। आतंकवाद के बहाने अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले को भारत सरकार के समर्थन और इसे लेकर मीडिया के जरिये साम्प्रदायिक अन्धराष्ट्रवादी जुनून पैदा करने की कोशिशों के बावजूद देश भर में मज़दूरों-किसानों, बुद्धिजीवियों, छात्रों-नौजवानों, संस्कृतिकर्मियों ने इस हमले के खिलाफ जुलूस-रैलियां निकालीं, सभाएं आयोजित कीं और युद्ध विरोधी प्रचार अभियान निकाला। दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर में अन्य प्रगतिशील, जनपक्षधर साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों के साथ मिलकर बिगुल मज़दूर दस्ता, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, नारी सभा व राहुल फाउण्डेशन ने साम्राज्यवादी युद्ध विरोधी कार्यक्रमों में भागीदारी की।

दिल्ली में ए.आई.पी.आर.एफ., इप्टू, अखिल भारत नेपाली एकता समाज, अंकुर, बिगुल मज़दूर दस्ता, डी.एस.यू., दिल्ली प्रदेश मज़दूर जनसंगठन, दिशा छात्र संगठन, जनहस्तक्षेप, झुग्गी-झोपड़ी संघर्ष समिति, मेहनतकश मज़दूर मोर्चा, मज़दूर एकता कमेटी, पीपुल्स फ्रंट, पी.एस.यू., पी.एम.टी.यू., राहुल फाउण्डेशन, संधान, सहेली स्त्री अधिकार संगठन, टी.यू.सी. आई., वर्कर्स सालिडेरिटी और अनेक प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने मिलकर **जंग रोको अभियान** नामक एक साझा अभियान चलाया। इसके तहत अब तक दो युद्ध विरोधी प्रदर्शन आयोजित किये गये हैं जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। साथ ही पर्चा वितरण अभियान के तहत विभिन्न नुक्कड़ों और मज़दूरों की बस्तियों में अब तक लगभग 25 हज़ार पर्चे बांटे जा चुके हैं। पर्चा बांटने पर देशद्रोह जैसे गम्भीर "अपराध" के तहत गिरफ्तार किये गये डी.एस.यू. के छह कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भी जंग रोको अभियान ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और रैली निकाली।

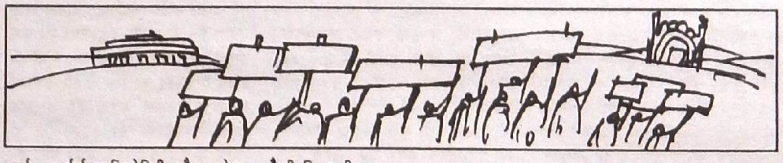

इसी तरह लखनऊ में भी इप्टा, राहुल फाउण्डेशन, जनसंस्कृति मंच, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जनसंघर्ष मोर्चा, नारी सभा, एपवा, महिला फेडरेशन, जनवादी महिला समिति, साझी दुनिया, वामा, वनांगना, आशा, दिशा छात्र संगठन, आइसा, एस.एफ.आई, ए.आई.एस.एफ., इंकलाबी नौजवान सभा; दायित्वबोध मंच, बिगुल मज़दूर दस्ता, अखिल भारतीय डाक लेखा कर्मचारी संघ, खनिज निगम संघर्ष समिति, बीमा कर्मचारी संघ, नगर शाखा लखनऊ, टी.यू.सी.आई., जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जैसे जनसंगठनों व प्रगतिशील युद्ध विरोधी अन्य बुद्धिजीवियों ने **युद्ध विरोधी जन अभियान** नामक अभियान के तहत रैली और व्यापक पर्चा वितरण का आयोजन किया।

इसी तरह गोरखपुर में भी दिशा छात्र संगठन, नारी सभा और ए.आई.पी.आर.एफ. ने मिलकर एक पर्चा निकाला और उसका वितरण किया।

इसके अलावा देश भर में लुटेरे साम्राज्यवादी युद्ध और भारत सरकार द्वारा इसे समर्थन देने के खिलाफ रैलियों-प्रदर्शनों की खबरें हैं। इन युद्ध विरोधी जन कार्रवाइयों से यह बात बिल्कुल साफ है कि भले ही समाज के एक हिस्से में मीडिया के प्रचार से अन्धराष्ट्रवादी लहर मौजूद है, लेकिन मेहनतकश आबादी के बीच इन दुष्प्रचारों का कोई खास असर नहीं है। औद्योगिक मज़दूरों की बस्तियों में सरकारी अन्धराष्ट्रवादी प्रचार का असर सबसे कम दिखा। मज़दूर यह बखूबी समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले के पीछे छिपे असली साम्राज्यवादी मंसूबे क्या हैं और किस तरह लुटेरे शासक वर्गों के लिए आतंकवाद जनता के अधिकारों पर हमला करने का एक बहाना बन गया है।

पोटो के खिलाफ जनमोर्चा

दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा खतरनाक आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटो) लागू करने के खिलाफ पिछले 20 नवम्बर को दिल्ली में अनेक जनसंगठनों व स्वतंत्र बुद्धिजीवियों ने **पोटो के खिलाफ जन मार्च** का आयोजन किया। मार्च मंडी हाउस से चलकर जन्तर-मन्तर तक पहुंचा, जहां धरना दिया गया। धरना स्थल पर सभा के अतिरिक्त दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने **'ताला जुबान पर'** शीर्षक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया और डी.एस.यू. के कार्यकर्ताओं ने क्रान्तिकारी समूह गान प्रस्तुत किये।

इस मार्च और जुलूस में शामिल लोग 'आतंकवाद बहाना है, जनता ही निशाना है', 'भाजपा सरकार का एक ही मन, दमन-दमन-दमन!' आदि नारे लगा रहे थे। जुलूस के आगे-आगे चल रहा 'पोटो' का दानव लोगों के आकर्षण का केन्द्र था।

धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि आतंकवाद कुचलने के नाम पर 'पोटो' में सत्ता के किसी भी किस्म के विरोध को कुचलने और जनता पर सरकारी आतंक थोपने का पक्का इंतजाम किया गया है। सरकार की नीतियों या उसके किसी निर्णय का विरोध करने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इस अध्यादेश से बेमानी हो गया है।

वक्ताओं ने कहा कि आज देश में असंतोष बढ़ रहा है। लुटेरी आर्थिक नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठते जनांदोलनो के खिलाफ ही इस कानून का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाएगा, यह टाडा के उदाहरण से साफ है।

जुलूस के आगे चल रहा 'पोटो' का दानव लोगों के आकर्षण का केन्द्र था।

जुलूस और धरने में दिशा छात्र संगठन, डेमोक्रेटिक स्टुडेंट्स यूनियन, राहुल फाउण्डेशन, मेहनतकश मज़दूर मोर्चा, बिगुल मज़दूर दस्ता, वर्कर्स सालिडेरिटी, दिल्ली जनवादी अधिकार मंच, ए.आई.एफ.टी.यू, दिल्ली प्रदेश मज़दूर जनसंगठन, टी.यू.सी.आई आदि संगठनों के कार्यकर्ता शामिल थे।

अमेरिकी हुक्मरानों की ललचाई नजरें कैस्पियन सागर के तेल भण्डारों पर...

(पेज । से आगे)

नहीं है। अमेरिकी बमवर्षक विमानों के "चूक गये निशाने" दुनिया के महाबली की अचूक संहारक क्षमता की पोलपट्टी खोलने से कहीं ज़्यादा उसके मंसूबों की पोलपट्टी खोलकर रख दे रहे हैं। इन "चूक गये निशानों" से पल भर में अस्पताल श्मशान में बदल जा रहे हैं, जगमग बस्तियां अंधेरे में डूब जा रही हैं, पलायन कर रहे लोगों की सैकड़ों गाड़ियां कोयले में बदल जा रही हैं...। वही भयानक दृश्य ... हिरोशिमा-नागासाकी, वियतनाम, इराक, पनामा, ग्रेनाडा ...। तमाम पुराने और नये खौफनाक मंजर एक साथ मिलकर अमेरिकी हत्यारों के मानवतावाद और "अमेरिकी जीवन शैली" के गौरव गान की कलई खोलकर रख दे रहे हैं।

लेकिन हज़ारों बेगुनाह अफ़गानों को मौत के घाट उतार देने और काबुल, कन्धार, हेरात, जलालाबाद आदि शहरों को बंजर-वीरान बना देने के बाद भी अभी खुद अमेरिकी हुक्मरानों को अपनी राह आसान नज़र नहीं आ रही है। एक तो तालिबानों की छापामार लड़ाई की क्षमता और सोवियत साम्राज्यवादी कब्जे का हश्र उन्हें अभी भी बेचैन किये हुए है। दूसरे, नार्दन एलाएंस में शामिल कबीलों के युद्ध सरदारों और अन्य कबीलों का जो भी गंठजोड़ आज सरकार में बैठेगा वह कल तालिबान की तरह अमेरिका का कान नहीं चबायेगा, इसके बारे में अमेरिकी हुक्मरान आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए, उन्होंने अपनी पिट्ठू सरकार बनवाने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया है।

काबुल में अपनी मनमाफिक सरकार बनवाने के लिए अमेरिका ही नहीं समूची पश्चिम दुनिया के लुटेरे व रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान के शासक भी अपनी औकात भर कवायद कर रहे हैं। इस कवायद के पीछे किसी की चिन्ता यह नहीं है कि अफ़गानी जनता को एक अच्छी सरकार मिले, या उसमें ताज़िक, उजबेक, हज़ारा या पश्तून – सभी कबीलों को प्रतिनिधित्व मिले – सबकी चिन्ता सिर्फ एक है अपने-अपने आर्थिक-राजनीतिक और फौजी हित। वैसे भी किसी भी मुल्क में जनता की सरकार दुनिया के लुटेरों की तीन-तिकड़म या पंच फैसला सुनाने से नहीं बना करती। यह उस मुल्क की जनता के अपने संघर्षों की देन होती है।

काबुल से तालिबान के पीछे हट जाने से मध्ययुगीन बर्बरताओं से जो भी तात्कालिक राहत अफ़गानी जनता को महसूस हो रही हो, लेकिन यह उसके दुर्भाग्य का अन्त नहीं है। कबायली आधार पर संगठित नार्दन एलाएंस के विभिन्न गुटों के बीच की आपसी खींचतान और भीषण खूनखराबों की हदों तक पहुंच जाने वाली दुश्मनियां भी जगजाहिर हैं। ऐसे में जब तक अफ़गानिस्तान में विभिन्न कबीलों की आम मेहनतकश आबादी को एक मजबूत डोर में बांधने वाली कोई क्रान्तिकारी ताकत नहीं उभरती तब तक अफ़गानी जनता अपने दुर्भाग्य से अन्तिम तौर पर छुटकारा नहीं पा सकती। यह चाहे जब हो, लेकिन अफ़गानी जनता की त्रासदी से मुक्ति की राह यही है। मुसीबतें, परेशानियां और जटिलताएं चाहे जितनी हों जनता अपनी राह निकाल ही लेती है।

दूसरी ओर, दक्षिण एशिया का मेहनतकश अवाम भी इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी दखलन्दाजी को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले से ही साम्राज्यवादी लूट-खसोट का शिकार यहां का मेहनतकश अवाम अपने शासकों की साम्राज्यवादपरस्ती को भी समझता जा रहा है और उसके खिलाफ जगह-जगह आवाजें भी उठा रहा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में भी साम्राज्यवादी मंसूबों को आसानी से कामयाबी नहीं मिलने वाली।

विश्व व्यापार के चौधरियों के आगे सरकार ने घुटने टेके

(पेज । से आगे)

पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देशी दवा कम्पनियों के मालिक अपने मुनाफे में कटौती कर इस रियायत का लाभ जनता को नहीं देने वाले।

जिस दूसरी रियायत का ढोल पीटा जा रहा है वह फिलहाल सिर्फ आश्वासन के स्तर पर है। यह रियायत है कि नये चक्र की वार्ता के समय पुराने मुद्दों को निपटाया जायेगा। दुनिया के लुटेरों के आश्वासनों का क्या मोल होता है इसे बताने की जरूरत नहीं। निचोड़ यह कि विश्व व्यापार संगठन की पिछली तीन बैठकों की तरह इस बार भी (सिएटल को छोड़कर जिसमें मुख्यत: अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के बीच कृषि सब्सिडी और कुछ अन्य मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण बैठक असफल हो गयी थी।) बैठक में वही हुआ जो विश्व व्यापार के चौधरी चाहते थे।

इस बैठक में अमेरिका व यूरोपीय संघ के बीच कृषि सब्सिडी के मसले पर समझौते की खबरें आयी हैं। यूरोपीय संघ के देश अपने किसानों की सब्सिडी कम करने पर राजी हो गये हैं, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को क्या गंवाना पड़ा है यह बहुत साफ नहीं हो सका है। दरअसल दुनिया के पूंजीवादी मीडिया ने दोहा बैठक की खबरों पर जिस तरह की लीपापोती की उससे बैठक की अब तक साफ तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ सकी है।

लेकिन हमारे देश और दुनिया की मेहनतकश जनता के लिए यह बात बहुत अहम है भी नहीं कि दोहा बैठक में ठीक-ठीक क्या हुआ। दोहा में मेहनतकशों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे। वहां पहुंचे थे दुनिया की मेहनतकश जनता के लुटेरों के प्रतिनिधि। विश्व व्यापार संगठन इन्हीं का मंच है। इस मंच की बैठकों में ये लुटेरे यही तय करते हैं कि दुनिया की मेहनतकश जनता की लूट का बंटवारा कैसे किया जाये। इसके लिए जमकर सौदेबाजियां होती हैं। बड़े लुटेरे छोटे लुटेरों को डराते-धमकाते हैं, बांह मरोड़ते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। छोटे लुटेरे रिरियाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आरजू-मिन्नत करते हैं, मजबूरियों का रोना रोते हैं, जिसके बदले में कुछ टुकड़े फेंककर उन्हें चुप करा दिया जाता है। दोहा में भी यही हुआ है।

इस बैठक में चीन को भी विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कम्युनिस्ट नामधारी, चीन की मेहनतकश जनता के लुटेरे ये शासक भी अब लुटेरों की इस पंचायत में बैठकर सौदेबाजियां किया करेंगे। इस तरह अपने देश की मेहनतकश जनता को खुद लूटने के साथ ही साम्राज्यवादी लुटेरों को भी लूटने की और खुली छूट देंगे और बदले में दूसरे देशों की जनता को भी अपनी औकात भर लूटेंगे।

दोहा बैठक से यह जाहिर हो गया है कि जब अगले चक्र की वार्ता शुरू होगी तो भारत जैसे गरीब देशों की मेहनतकश जनता पर देशी-विदेशी लूट का शिकंजा और कसेगा। साम्राज्यवादी लुटेरे बहुपक्षीय निवेश, सरकारी खरीद में पारदर्शिता, व्यापार में श्रम एवं पर्यावरण मानकों को लागू करवाने के जरिये अपनी लूट का दायरा बढ़ायेंगे और देशी पूंजीपति लुटेरे विश्व बाज़ार में होड़ में टिके रहने के लिए देश की मेहनतकश जनता की हड्डियां और निचोड़ेंगे। छंटनी, तालाबन्दी, ठेकाकरण और तेज होगा। इसके साथ ही, देश के छोटे-मंझोले किसानों की तबाही का एक नया दौर भी शुरू होगा। इसका नतीजा यह होगा कि देश की मेहनतकश आबादी और अच्छी तरह समझेगी कि पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूट के विश्वव्यापी जाल को छिन्न-भिन्न किये बिना उनकी तबाही-बर्बादी का दौर नहीं खत्म होगा।

विशेष सामग्री

(दसवीं किश्त)

पार्टी की बुनियादी समझदारी

अध्याय - 4

पार्टी की बुनियादी कार्य दिशा

एक क्रांतिकारी पार्टी के बिना मजदूर वर्ग क्रांति को कतई अंजाम नहीं दे सकता। लेनिन ने इस बात को बार-बार जोर देकर कहा था। स्तालिन और माओ ने भी बराबर इस बात पर जोर दिया और बीसवीं सदी की सभी सफल सर्वहारा क्रान्तियों ने भी इसे सत्यापित किया।

लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी के सांगठनिक उसूलों का निर्धारण किया और इसी फौलादी सांचे में बोल्शेविक पार्टी को ढाला। चीन की पार्टी भी बोल्शेविक पार्टी की ही उत्तराधिकारी थी। सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान, समाजवादी समाज में वर्ग-संघर्ष का संचालन करते हुए माओ के नेतृत्व में चीन की पार्टी ने अन्य युगान्तरकारी सैद्धान्तिक उपलब्धियों के साथ-साथ लेनिनवादी सांगठनिक सिद्धान्तों को भी और आगे विकसित किया।

सोवियत संघ और चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के लिए बुर्जुआ तत्वों ने सबसे पहले यही जरूरी समझा कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी का चरित्र बदल दिया जाये। हमारे देश में भी संसदीय रास्ते की अनुगामी नामधारी कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय मजदूर क्रांति को सफल बनाने के लिए भारत में भी सर्वहारा वर्ग की एक सच्ची क्रान्तिकारी पार्टी खड़ी करने का काम सर्वोपरि है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि मजदूर वर्ग यह जाने कि असली और नकली कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है और एक क्रान्तिकारी पार्टी कैसे खड़ी की जानी चाहिए।

इसी उद्देश्य से, फरवरी, 2001 अंक से हमने एक बेहद जरूरी किताब 'पार्टी की बुनियादी समझदारी' के अध्यायों का किश्तों में प्रकाशन शुरू किया है। इस अंक में दसवीं किश्त दी जा रही है। यह किताब सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान पार्टी-कतारों और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए तैयार की गयी श्रृंखला की एक कड़ी थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेस (1973) में पार्टी के गतिशील क्रान्तिकारी चरित्र को बनाये रखने के प्रश्न पर अहम सैद्धान्तिक चर्चा हुई थी, पार्टी का नया संविधान पारित किया गया था और संविधान पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। इसी नई रोशनी में यह पुस्तक एक सम्पादकमण्डल द्वारा तैयार की गयी थी। मार्च, 1974 में पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, शंघाई से इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की 4,74,000 प्रतियां छपीं। यह पुस्तक पहले चीनी भाषा से फ्रांसीसी भाषा में अनूदित हुई और 1976 में प्रकाशित हुई। फिर नार्मन बेथ्यून इंस्टीच्यूट, टोरण्टो (कनाडा) ने इसका फ्रांसीसी से अंग्रेजी में अनुवाद कराया और 1976 में ही इसे प्रकाशित भी कर दिया। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पुस्तक के इसी अंग्रेजी संस्करण से किया गया है।

- सम्पादक

हमें "निर्णायक कड़ी" और "सम्पूर्ण श्रृंखला" के बीच के सम्बन्ध को सही ढंग से संभालना चाहिए

पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को लागू करने में दृढ़ बने रहने के लिए, यह आवश्यक है कि "निर्णायक कड़ी" "श्रृंखला" को निर्देशित करें। दूसरे शब्दों में, पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा और ठोस कामों और ठोस कदमों के लिए कार्यदिशा के संबंध को सही ढंग से संभालना जरूरी है।

अपने आप में ही कार्यदिशा का सवाल सैद्धान्तिक अधिरचना का हिस्सा होता है, लेकिन चूंकि यह सार रूप में, एक निश्चित वर्ग के हितों उसकी आकांक्षाओं और विश्व-दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह उस बुनियादी सिद्धान्त का निर्माण करती है जो सभी कामों का मार्गदर्शन करता है। पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा ही हमें इस काबिल बनाती है ताकि हम समाजवाद के कालखण्ड के प्रधान अन्तरविरोधों को हल कर सकें, और इसीलिए यह प्राधिकार की स्थिति में होती है। यह क्रांति और निर्माण दोनों में ही महत्वपूर्ण होती है और हमारे कार्यों में बुनियादी सिद्धान्त का निर्माण करती है।

अध्यक्ष माओ ने कहा है: **"कार्यदिशा ही नियंत्रक कड़ी है; एक बार यह पकड़ में आ जाए तो हर चीज़ उपयुक्त स्थान पर आ जाती है।"** (*पीकिङ रिव्यू में उद्धृत, सं-1, 7 जनवरी, 1972, पृ.-10*) सभी पार्टी संगठनों और सदस्यों को पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को भारी महत्व देना चाहिए और "निर्णायक कड़ी" को "सम्पूर्ण श्रृंखला" की कमान में रखना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मोर्चे पर हमारे कामरेड काम कर रहे हैं – उद्योग, कृषि, वाणिज्य, वित्त, संस्कृति और शिक्षा – जब वे एक ठोस लक्ष्य की पूर्ति में लगे हों, तो उन्हें हमेशा स्वयं से पूछना चाहिए कि वे अपने काम में पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा द्वारा निर्देशित हैं या नहीं, और यह कि वे समाजवाद और सर्वहारा वर्ग के बुनियादी हितों की व्यापक दिशा के साथ मेल रखते हुए काम कर रहे हैं या नहीं। अगर हम पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को भूलते हैं और सिर्फ ठोस कामों और ठोस कदमों की कार्यदिशा से सरोकार रखते हैं – संक्षेप में यदि हम "निर्णायक कड़ी" को भूलते हुए अपना सरोकार माल "श्रृंखला" से रखते हैं, तो हम ऐसे क्रांतिकारी बन जाते हैं जो सोच में बिना किसी स्पष्टता के आंख बन्द करके काम करते हैं, और यह खतरा होता कि चीज़ों को देखने का हमारा दृष्टिकोण अधिकाधिक अदूरदर्शी हो। जब हम किसी समस्या पर गौर करते हैं, हम सिर्फ इससे जुड़ी विभिन्न परिघटनाओं को देखते हैं, बिना सार समझे हुए, हम जनता और पार्टी के दीर्घकालिक हितों के बारे में सोचे बिना, सिर्फ तात्कालिक हितों को देखते हैं तब हम कार्यदिशा पर आधारित चीज़ों और उन चीजों के बीच, जो कार्यदिशा से मेल नहीं खातीं, भेद कर पाने में असक्षम हो जाते हैं। इस तरीके से न केवल हम ठोस काम कर पाने में असक्षम हो जाते हैं, बल्कि हम दिशा-बोध खोकर पथभ्रष्ट हो जाने का जोखिम भी उठाते हैं, और यह बहुत खतरनाक है।

पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को "निर्णायक कड़ी" के रूप में पक्की तौर पर समझने का यह अर्थ कतई नहीं है कि ठोस कार्यों और कदमों की उपेक्षा की जाए। अगर हम वस्तुतः ठोस कामों और कदमों को पूरा नहीं करते तो, पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा का कार्यान्वयन एक अर्थहीन अभिव्यक्ति बन जाएगा। इसलिए सभी पार्टी संगठनों और सदस्यों को जो पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा द्वारा निर्देशित हैं – अधिक से अधिक अध्ययन और जांच-पड़ताल जरूर ही करनी चाहिए और कर्तव्यनिष्ठा के साथ सभी ठोस कामों को करने के लिए जनता पर भरोसा करना चाहिए। पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा के कार्यान्वयन और विभिन्न ठोस कामों को घनिष्ठता के साथ जोड़कर, संघर्ष-आलोचना-रूपांतरण आंदोलन को उचित ढंग से चलाते हुए ही, हम सभी बुनियादी इकाइयों में सर्वहारा की तानाशाही के सशक्तीकरण के लक्ष्य को पूरा कर पाने में सक्षम होंगे।

हर कम्युनिस्ट को हर समय, सभी कामों में पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को दिमाग में रखना चाहिए, दो लाइनों के संघर्ष की अपनी चेतना का लगातार उन्नयन करना चाहिए और पार्टी की बुनियादी कार्यदिशा को लागू करने और उसकी रक्षा करने में एक दृढ़ संकल्प योद्धा के रूप में काम करना चाहिए।

(क्रमशः)

मजदूर साथियों से चन्द दो टूक बातें-एक सीधा आह्वान

सम्पादक की ओर से

साथियों,

पिछले कई वर्षों से 'बिगुल' लगातार आपके हाथों में पहुंच रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर मेहनतकश अवाम ने इसका स्वागत किया है और अपने इंकलाबी अखबार के रूप में इसे अपनाया है, पर हम इससे बहुत अधिक की आप से उम्मीद रखते हैं।

'बिगुल' सही मायने में क्रांतिकारी मजदूर अखबार तभी बन सकता है, जब आप स्वयं कलम उठायें और इसके बारे में तफ़सील के साथअपनी राय लिख भेजें। आप इसकी कमियों-कमजोरियों के बारे में हमें समझाकर बताइये और जाहिरा तौर पर, यह भी बताइये कि आपको इसमें क्या-क्या अच्छा लगा।

और यही नहीं, हम यह भी चाहते हैं आप अपने कारखाने,वर्कशाप या काम की पूरी परिस्थितियों के बारे में, उनकी हर किस्म की छोटी-बड़ी, कठिनाइयों के बारे में,मालिक, सुपरवाइजर, फोरमैन के व्यवहार के बारे में, काम के घंटों और सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में रिपोर्ट तैयार करके भेजिए। आपके यहां वेतन संशोधन, महंगाई भत्ता ओवरटाइम आदि की क्या स्थिति है? लेबर कोर्टों में कितने मामले हैं? छंटनी-तालाबंदी आदि की क्या स्थिति हैं? मालिकों-अफसरों का रवैया उदार है या दमनकारी? किसी न किसी तरह से सताये जा रहे मजदूर को लेबर कोर्ट से क्या इंसाफ मिला है या मिल पाता है?

इस मामले में ट्रेड यूनियनों की क्या भूमिका है? उनके नेताओं की क्या भूमिका है? वे आन्दोलन और संघर्ष द्वारा मालिकों पर कुछ दबाव बनाते हैं या कि वल समझौता- वार्ताओं-मध्यस्थताओं-दलाली की राजनीति करते हैं? इन ट्रेड यूनियनों की राजनीतिक भूमिका क्या है? ये तमाम संसदीय पार्टियों से जुड़ी हैं या कुछ स्वतंत्र भी हैं? किन-किन कारणों से ये अलग-अलग हैं और मजदूरों को भी बांट रखा है? यानी इनके आपसी मतभेद के मुद्दे क्या हैं? आपके ख्याल से ट्रेड यूनियन आन्दोलन की स्थिति क्या है? यह तरक्की कर रहा है या इसमें गिरावट आ रही है? आप ट्रेड यूनियनों से क्या चाहते हैं? क्या आज ये मजदूर वर्ग के राजनीतिक संघर्षों की एक अनिवार्य पाठशाला की भूमिका निभा पा रही हैं? हमें इन सभी मसलों पर आपसे जानकारी चाहिए और आपकी राय चाहिए?

आप समाजवाद, सर्वहारा क्रांति और मजदूर राज के बारे में क्या सोचते हैं? आपके ख्याल से इस ओर आगे बढ़ने यानी पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के खिलाफ फैसलाकुन लड़ाई में ट्रेड यूनियन आन्दोलन क्या भूमिका निभायेगा और किस प्रकार?

पूरे देश के पैमाने पर उदारीकरण और निजीकरण की नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद से करोड़ों मजदूर बेकार हो चुके हैं, पुराने कारखाने बंद होते जा रहे हैं, गरीब और मध्यम किसान अपनी जगह-जमीन से उजड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीना जा रहा है। आपके कारखाने, शहर, गांव या इलाके की क्या स्थिति है? पिछले सात-आठ वर्षों में क्या-क्या विशेष बदलाव आये हैं? हम आपसे यह जानकारी भी विस्तार से चाहते हैं।

आप अपनी कालोनी या बस्तियों की स्थिति अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी की परेशानियों-समस्याओं के बारे में भी विस्तार से 'बिगुल' के लिए रपटें तैयार करके भेजिए।

'बिगुल' वेतन भोगी पत्रकारों-कर्मचारियों-एजेण्टों के भरोसे चलने वाला अखबार नहीं है। मजदूर ही इसके सही संवाददाता हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं। मजदूर ही इसके वितरक, एजेण्ड और हाकर होंगे। यह मजदूरों के (और साथ ही मजदूर क्रांति के समर्थक प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के) सहयोग से प्रकाशित होता है। इसके सम्पादन और लेखन की टीम से जुड़े जो साथी मध्यमवर्गीय परिवारों से आये हैं, वे भी मजदूरों की जिन्दगी और संघर्षों से जुड़कर एकरूप हो जाने की प्रतिज्ञा किये हुए लोग हैं।

अतः 'बिगुल' द्वारा मजदूरों की क्रांतिकारी आवाज बुलन्द करने के लिए जरूरी है कि आप बिगुल के संवाददाता बनें, इसमें नियमित रपटें और लेख भेजें, इसमें छपी चीजों पर अपनी राय और सलाह भेजें, साथ ही अपने इलाके में इसका वितरण करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनतकशों तक इसे पहुंचायें।

बहुत जरूरी है कि 'बिगुल' को पसन्द करने वालों और इसके मकसद से सहमत मजदूरों को संगठित किया जाये और छोटे-छोटे ग्रुपों में इन्हें इकट्ठा करके मजदूर आन्दोलन, ट्रेड यूनियन आदि की समस्याओं तथा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों पर नियमित बातचीत की जाये तथा मेहनतकश क्रांतियों की समस्याओं, इतिहास, सिद्धान्त आदि पर कुछ पढ़ाई-लिखाई भी की जाये। यह छोटी सी शुरुआत एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी शुरुआत भी हो सकती है। पहली बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हममें एक नई शुरुआत करने का साहस हो, संकल्प हो और यह विश्वास हो कि यह दुनिया यहीं रुकी नहीं रहेगी।

पूरी दुनिया की सम्पदा के निर्माताओं को फिर से बगावत करनी ही होगी और बगावत से क्रांति की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। हमें इन हालात को बदलने के लिए इनको समझना है और इनको बदलने की जद्दोजहद के दौरान खुद को बदल लेना है। मजदूर वर्ग के नये क्रांतिकारी जागरण और नये क्रांतिकारी ज्ञानोदय का यहीं संदेश है।

●

कलकत्ता में 'अतिक्रमण हटाओ' अभियान में बर्बरता के नये कीर्तिमान

"ग़रीब परवर" "समतावादी" लालपताकाधारियों ने भेड़ की खाल में छुपे भेड़िये की कहानी दुहराई

ग़रीबों को महानगरों से उजाड़ने-खदेड़ने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की जो देशव्यापी मुहिम चल रही है, उसमें प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सितम्बर माह में कलकत्ता के टोलीनल्ला क्षेत्र में उसने न सिर्फ दो हज़ार लोगों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया, बल्कि साथ ही किसी भी प्रकार के पुनर्वास से साफ इन्कार कर दिया। उल्लेखनीय है कि यह कवि हृदय मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का चुनाव क्षेत्र है।

कलकत्ता के टोलीनल्ला क्षेत्र के निवासियों को बुद्धदेव भट्टाचार्य को वोट देते समय यह गुमान भी न रहा होगा कि यह नौटंकीबाज भद्रजन एक दिन उनके लिए बुलडोजर और रैपिड एक्शन फोर्स भेजेगा। दुर्गा पूजा के ठीक पहले अपने जनप्रतिनिधि से मिली इस सौगात को देखकर तो शायद शैतान भी शर्मसार हो जाये। भेड़ की खाल में छिपे भेड़िये की कहानी तो इन ग़रीब बस्तियों में कई बार कही सुनी गई होगी। लेकिन इस कहानी को ये ग़रीबों के रहनुमा होने का दम भरने वाले लाल पताकाधारी चरितार्थ कर देंगे, यह टोलीनल्ला के निवासियों ने न सोचा होगा।

आठ सितम्बर को वाममोर्चा सरकार ने फरमान जारी किया कि बेदखली का पहला चरण टोलीनल्ला (टाली का नाला) के किनारे बसे हुए क्षेत्र में 22 सितम्बर को शुरू होगा। यह गरिया स्टेशन से कुदघाट के बीच होना था। 25 सितम्बर को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपा, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि अतिक्रमणकारियों ने विकास कार्यों से सहयोग करते हुए "स्वेच्छापूर्वक" जगह खाली कर दी। गाल बजाकर और इश्तहार छपवाकर नंगी सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश करने वाले इन बेहयाओं को कौन समझाये कि सच्चाई इनकी ज़रखरीद गुलाम नहीं है।

सच्चाई यह है कि 22 सितम्बर को भारी पुलिसिया इंतजाम के बीच गाली, लात-घूंसों और लाठी के दम पर गरिया स्टेशन बस स्टैण्ड के बीच की बस्ती को उजाड़ दिया गया। जिलाधिकारी और उच्च पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। स्थानीय पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। 25 सितम्बर को गरिया बस स्टैण्ड से कुदघाट के बीच चले बेदखली के दूसरे चरण में पुलिस ज़्यादती की सारी हदें पार कर गई। लोगों को न सिर्फ मारा-पीटा गया, वरन उनके भोजन को फेंक दिया गया, उनके बिस्तरों पर पेशाब किया गया। इन दो दिनों में ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1150 परिवार इस बेदखली के शिकार हुए।

उजाड़े गये ज़्यादातर परिवार इस क्षेत्र में पिछले तीस-चालीस वर्षों से रह रहे थे। इनमें से अधिकांश के पास राशन कार्ड और बिजली के बिल हैं। यहां पर रहने वाली आबादी मुख्यत: मज़दूरी कर या छोटा-मोटा धंधा कर किसी तरह दो जून की रोटी जुगाड़ ले रही थी। लेकिन सरकारी निगाह तो इन्हें अतिक्रमणकारी और भू माफिया के रूप में ही पहचानती है। बेदखल किये गये परिवारों के बारे में एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में ढेरों परिवार ऐसे हैं जहां परिवार की मुखिया महिलाएं हैं। इनमें ज़्यादातर स्त्रियां प्रतिमाह हज़ार रूपये से ज़्यादा नहीं कमा पातीं, जिसमें उन्हें पूरे परिवार का खर्च चलाना होता है। बेदखली के बाद ऐसे परिवारों के सामने जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो गया है। क्योंकि कलकत्ता जैसी जगह में मुर्गी के दड़बे जैसी कोठरी भी पांच सौ रुपये से कम किराये पर नहीं मिल सकती।

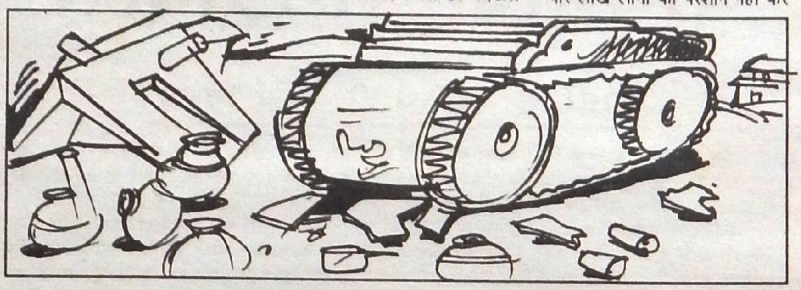

वाम मोर्चा सरकार ने पुनर्वास से साफ इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है "यदि मैं अभी (पुनर्वास) करता हूं, तो मुझे इसे बेदखल किये गये अतिक्रमणकारियों के लिए हर बार करना होगा।" जबकि हिन्दुस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बीस साल से किसी स्थान पर रह रहे लोगों को हटाने से पूर्व उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। टोलीनल्ला क्षेत्र के परिवार तो चालीस साल से इस इलाके में रह रहे हैं और उनके पास इस क्षेत्र के निवासी होने के कागज़ात हैं। मानवाधिकार की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, संसद-विधानसभा में बैठकर छाती पीटने वाले इन नकली वामपंथियों की आम इंसान की ज़िन्दगी के प्रति क्या सोच है इसे बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस बयान से समझा जा सकता है "मैं जानता हूं कि कुछ लोग तकलीफ में हैं, लेकिन मैं चार हज़ार लोगों के पीछे चार लाख लोगों को परेशान नहीं कर सकता।" यानी मेट्रो रेल में सफल करने वालों के लिए इन ग़रीब मज़दूरों को उजाड़ना ज़रूरी है।

अभी टोलीनल्ला के ग़रीबों को उजाड़ने के लिए सरकार के पास मेट्रो रेल का बहाना है। जैसे कि दिल्ली में ग़रीबों को उजाड़ने के लिए प्रदूषण को बहाना बनाया था। चूंकि पूंजीवादी सरकारें के लिए आम आदमी की ज़िन्दगी की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए उनकी ज़िन्दगियों से खिलवाड़ करने में वह पाशविक सुख प्राप्त करती है। इस मामले में समाजवाद की बात कहते हुए पूंजीपतियों की स्वामिभक्त वाममोर्चा सरकार भी पीछे नहीं है। उसकी बराबरी, समानता के क्या अर्थ हैं उसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि उसने टोलीनल्ला क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के ग़रीबों के सर से छत छीन ली। यहां पर पहले यह कहा गया था कि प्रस्तावित मेट्रो रेल के ईर्द-गिर्द 25 फीट तक के घरों को उजाड़ा जायेगा, किन्तु जब बेदखली अभियान शुरू हुआ तो सभी घरों को ढहा दिया गया। अधिकारियों का कहना था कि यह ग़ैरबराबरी होगी यदि किसी ग़रीब का घर ढहाया जाय और किसी को रहने दिया जाय।

टोलीनल्ला क्षेत्र में सरकारी अमले की असंवेदनशीलता, पुलिसिया दमन की क्रूरता का बयान शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। बेघर-बेदर ग़रीबों को लगातार परेशान किया जा रहा है। उजड़े हुए लोगों ने स्थानीय कुछ जनसंगठनों की मदद से एक 'साझा चूल्हा' 26 सितम्बर को गरिया में स्थापित किया था, जिसको पुलिस ने ऐन गांधी जयन्ती के दिन ढहा दिया। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी, पुलिस के भारी दमन को सहते हुए उन्होंने फिर वहां पर 'साझा चूल्हा' चलाया। अबकी पुलिस ने उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। पुलिस के उच्चाधिकारियों का मानना है कि यह 'ला एण्ड आर्डर' के लिए ख़तरनाक जगह है।

लाल पताकाधारियों द्वारा पीठ में छुरा भोंके जाने के बावजूद टोलीनल्ला की ग़रीब जनता लड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के तमाम जनसंगठनों ने मिलकर 'उच्छेद विरोधी जुक्त मोर्चा' बनाया है। मोर्चे ने संघर्ष के कई कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। चुनावबाज बाजीगर भी अपना खेल दिखाने और अपने वोटों की खातिर यहां आते रहते हैं, लेकिन इन चुनावबाज राजनीतिक पार्टियों में कितना ही मतभेद क्यों न दिखाई पड़ता हो आम जनता के ख़िलाफ अन्दरखाने में एकजुट रहते हैं। सोचा जा सकता है कि मेयर, तृणमूल कांग्रेस का है, मुख्यमंत्री सी.पी.आई (एम) का, लेकिन ग़रीबों को उजाड़ने पर एकमत हैं। साम्राज्यवादी संस्था एशियन विकास बैंक (ए. डी. बी.) से ऋण लेना है, साम्राज्यवाद-पूंजीवाद की सेवा करने की कसम खाई है तो टोलीनल्ला क्या किसी भी जगह कभी भी ग़रीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है।

– ललित

लोलबांध खान दुर्घटना

मजदूरों का भविष्य स्याह, मालिकों की जिंदगी रौशन

मुनाफे की अंधी हवस गरीबों की जान तक ले सकती है। एक बार फिर यह बहुत ही घिनौने रूप में साबित हुआ है।

पिछले दिनों 10 अक्टूबर को आसनसोल में हुए लोलबांध कोयला धंसान में 150 लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन प्रशासन ने उन खान मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकालने की दिशा में अब तक कुछ नहीं किया है। हां, खान मालिक और जिला प्रशासन एक-दूसरे पर यह सवाल जरूर दाग रहे हैं कि किसकी खामियों की वजह से ऐसी दुर्घटना हुई।

आसनसोल के एस.पी. ने मलबे में फंसे मजदूरों की जान की बगैर चिंता किए अपने अधिकारियों को यह आदेश भी दे दिया कि अवैध खनन को रोका जाए ताकि कोयला चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। कोयला धंसान में फंसे लोगों के बारे में एस.पी. और उद्योग राज्यमंत्री का कहना है कि यह लोग अवैध रूप से कोयले की कटाई कर, उसकी चोरी कर रहे थे। क्या एस. पी. महोदय को यह मालूम नहीं कि यह मजदूर अवैध रूप से कोयला काटने का काम क्यों कर रहे थे। क्या यह मजदूर कोयले से अपना घर भरना चाहते थे या इन्हें अपनी जान जोखिम में डालने का शौक था? नहीं, अपने परिवार को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए उन्हें जानलेवा परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। "वैध" तरीके से जीने वाले एस.पी. महोदय को यह मालूम होना चाहिए कि अवैध तरीकों से जीने वाले इन मजदूरों के दाम पर ही उन जैसों की जिंदगी चल रही है।

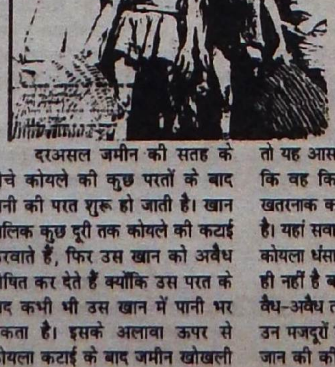

दरअसल जमीन की सतह के नीचे कोयले की कुछ परतों के बाद पानी की परत शुरू हो जाती है। खान मालिक कुछ दूरी तक कोयले की कटाई करवाते हैं, फिर उस खान को अवैध घोषित कर देते हैं क्योंकि उस परत के बाद कभी भी उस खान में पानी भर सकता है। इसके अलावा ऊपर से कोयला कटाई के बाद जमीन खोखली हो जाने से कभी भी इसके धंसने की संभावना रहती है। खान मालिक द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद उस खान को ठेकेदार अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय भी खान मालिक की ही तरफदारी करता है उसे कोयला मजदूरों के जान की सलामती की चिंता नहीं रहती है।

वैसे भी कोयलांचल में जब एक खान मजदूर प्रवेश करता है तो उसे पता नहीं होता कि वह जीवित वापस लौट भी पाएगा या नहीं क्योंकि कभी भी भू-धंसान हो जाने, खान में पानी भरने और गैस रिसाव की संभावना लगातार बनी रहती है। जिस खान को अवैध घोषित कर दिया हो, अगर वहां कोई मजदूर काम कर रहा हो तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि वह कितना मजबूर होगा, जो ऐसे खतरनाक कामों के लिए भी तैयार रहता है। यहां सवाल आसनसोल को लोलबांध कोयला धंसान में 150 लोगों के फंसे का ही नहीं है बल्कि सभी कोयला खानों में वैध-अवैध तरीके से कोयला निकाल रहे उन मजदूरों के भविष्य का है जो अपनी जान की कीमत पर अपने मालिकों की जिंदगी को रौशन करते हैं।

●

प्रधानमंत्री जी को दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान चक्षु खुले

(बिगुल संवाददाता)

पिछले महीने अचानक प्रधानमंत्री जी को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की अनदेखी की जा रही है और उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलते हुए पूंजीपतियों से थोड़ा "मानवीय" होने की अपील की।

अब तो देश के समूची ग्रामीण आबादी के दुख-दर्द दूर होने के दिन करीब आ रहे हैं क्योंकि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (एसोचेम) और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की शिखर बैठक में प्रधानमंत्री जी ने कहा "निजी क्षेत्र को अपने मुनाफे का एक हिस्सा धर्मार्थ के रूप में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में खर्च करना चाहिए।" गरीबों को सब्जबाग दिखाने वाले आर्थिक सुधारों के नतीजों की क्रूरता सामने आने के बाद यह अनायास नहीं है कि अब प्रधानमंत्री जी उद्योगपतियों के हृदय परिवर्तन की बातें कर रहे हैं।

आर्थिक-सुधारों का फायदा गांवों तक पहुंचाने की "चिन्ता" के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उद्योग की भी है क्योंकि ऐसा होने पर उद्योग के लिए भी व्यापारिक अवसर बढ़ेंगे। क्या खूब बात कही है प्रधानमंत्री जी! दान से भी मुनाफा कमाना चाहते हैं?

और तो और केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू तो एक कदम और आगे बढ़ गये जब उन्होंने कहा "देश में 21700 गांवों में पीने का पानी नहीं है, 80 हजार गांवों में बिजली नहीं है, 1 लाख गांवों में स्कूल भवन नहीं है, 50 फीसदी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, 72 फीसदी आबादी में से 27 फीसदी ग़रीबी रेखा के नीचे है। शहर और गांवों के इस अन्तर को सड़कें अस्पताल, संचार, शिक्षा आदि उपलब्ध कराकर भरा जाना चाहिए। देश में कुल पांच लाख कम्पनियां और छह लाख गांव हैं। हर कम्पनी को एक या ज्यादा गांवों को गोद लेकर उसका विकास करना चाहिए।" इसके पहले नायडू साहब को देश के गांवों की दुर्दशा नहीं दिखाई दी, और न ही उन गांवों को गोद लेने वाली कम्पनियां।

दरअसल,यह सारी कसरत गांवों में पूंजी निवेश करके मुनाफा निचोड़ने के लिए ही की जा रही है, तभी तो प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास पर भी जोर दे रहे हैं। उद्योगपतियों के हितों के मद्देनज़र शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के लागू करने के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग क्षेत्र के व्यापारिक अवसरों को बढ़ाने के लिए ही "दान" और "त्याग" की बातें की जा रही हैं। और यही है प्रधानमंत्री जी को अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त होने और उनके ज्ञान चक्षु खुलने का राज।

महान अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति की 84वीं वर्षगांठ पर

मज़दूर क्रान्ति ही साम्राज्यवादी युद्धों का नाश करेगी!

व्ला. इ. लेनिन

... साम्राज्यवादी युद्धों का प्रश्न, वित्तीय पूंजी की इस समय सारे संसार पर हावी अंतर्राष्ट्रीय नीति का प्रश्न, जो **अनिवार्यत:** नये साम्राज्यवादी युद्धों को जन्म देती है, जो अनिवार्यत: जातीय उत्पीड़न, मुट्ठी भर "अग्रगामी" शक्तियों द्वारा कमजोर, पिछड़ी हुई, छोटी राष्ट्रीयताओं पर डाका डाले जाने, उनकी लूट-खसोट किये जाने, उनका गला घोंटे जाने की कार्रवाइयों की अश्रुतपूर्व उग्रता को जन्म देती है – यह प्रश्न 1914 से पृथ्वी के समस्त देशों की सारी नीति की आधारशिला का प्रश्न रहा है। यह लाखों-करोड़ों लोगों की ज़िन्दगी और मौत का प्रश्न है। यह प्रश्न इस बात का है कि क्या अगले साम्राज्यवादी युद्ध में, जिसकी बुर्जुआ जन हमारी आंखों के सामने तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने पूंजीवाद में से जन्म ले रहा है, दो करोड़ मनुष्य मौत के घाट उतारे जायेंगे (बजाय एक करोड़ के, जो 1914-18 के युद्ध में और अभी तक ख़त्म न हुए अनुपूरक "छोटे" युद्धों में मारे गये थे) या नहीं, क्या इस अनिवार्य (यदि पूंजीवाद बरक़रार रहता है) आगामी युद्ध में 6 करोड़ मनुष्य अपंग होंगे (बजाय तीन करोड़ के, जो 1914-18 के युद्ध में अपंग हुए थे) या नहीं। और इस प्रश्न में भी हमारी अक्तूबर क्रान्ति ने विश्व इतिहास में एक नये युग का उद्घाटन किया। समाजवादी-क्रान्तिकारियों और मेंशेविकों के रूप में, सारे संसार के सभी टुटपुंजिया, नामधारी "समाजवादी" जनवादियों के रूप में बुर्जुआ वर्ग के चाकर और उसके सुर में सुर मिलाने वाले लोग "साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध में बदल दो" के नारे का मखौल उड़ाया करते थे। परंतु यह नारा एकमात्र सत्य सिद्ध हुआ – अप्रिय, दो टूक, नग्न, निर्मम, परन्तु इन सबके बावजूद सर्वाधिक परिष्कृत अंधराष्ट्रवादी तथा शांतिवादी धोखाधड़ियों के ढेर के बीच सत्य। इन धोखाधड़ियों की दीवारें ढह रही हैं। ब्रेस्त शांति-संधि की कलई खुल गयी। हर गुजरता दिन ब्रेस्त शांति-संधि से भी बदतर वेर्साई शांति-संधि के महत्व तथा परिणामों की कलई अधिकाधिक निर्ममतापूर्वक खोलता जा रहा है। बीते कल के युद्ध के कारणों के बारे में और समीप आते जा रहे आगामी कल के युद्ध के बारे में सोच-विचार करने वाले करोड़ों-करोड़ लोगों के समक्ष यह भयावह सत्य अधिकाधिक स्पष्ट, अधिकाधिक प्रत्यक्ष, अधिकाधिक अटल रूप से प्रकट हो रहा है: **बोल्शेविक संघर्ष तथा बोल्शेविक क्रान्ति के अतिरिक्त और किसी भी तरह** साम्राज्यवादी युद्ध से और उसे अनिवार्यत: जन्म देने वाले साम्राज्यवादी संसार (यदि हमारे यहां पुराना वर्ण-विन्यास होता, तो मैं यहां दो शब्द "मीर"* – उनके दोनों अर्थों में – लिखता) से, इस नरक से छुटकारा नहीं पाया जा सकता।

बुर्जुआ जनों तथा शांतिवादियों, जनरलों तथा टुटपुंजियों, पूंजीपतियों तथा कूपमंडूकों, सारे ईसाई धर्मात्माओं तथा दूसरे और ढाईवें इंटरनेशनल** के सभी सूरमाओं को क्रोधोन्मत्त होकर इस क्रान्ति को गालियां देने दें। द्वेष, कुत्सा और झूठ की कोई बौछार इस विश्व-ऐतिहासिक तथ्य को धुंधला नहीं कर सकती कि सैकड़ों-हज़ारों वर्षों में पहली बार दासों ने दास-स्वामियों के बीच होने वाले युद्ध का उत्तर खुलेआम यह नारा बुलंद करके दिया: अपने लूट के माल के बंटवारे के लिए दास-स्वामियों के बीच होने वाले इस युद्ध को सभी राष्ट्रों के दास-स्वामियों के विरुद्ध सभी राष्ट्रों के दासों के युद्ध में बदल डालो।

सैकड़ों-हज़ारों वर्षों में पहली बार यह नारा एक धुंधली और अशक्त आशा से सुस्पष्ट, साफ राजनीतिक कार्यक्रम में, सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में लाखों-लाख उत्पीड़ितों के कारगर संघर्ष में बदला, सर्वहारा वर्ग की पहली विजय में, युद्धों के खात्मे के ध्येय, विभिन्न राष्ट्रों के संघबद्ध बुर्जुआ जनों के, उन बुर्जुआ जनों के विरुद्ध, जो पूंजी के दासों की कीमत पर, उजरती मज़दूरों की कीमत पर, किसानों की कीमत पर, मेहनतकशों की कीमत पर मेल-मिलाप करते हैं और लड़ते हैं, समस्त राष्ट्रों के मज़दूरों की संघबद्धता के ध्येय की पहली विजय में बदला।

यह पहली विजय अभी अंतिम विजय नहीं है, और वह हमारी अक्तूबर क्रान्ति को अभूतपूर्व मुसीबतों और कठिनाइयों के साथ, अश्रुतपूर्व कष्टों के साथ, हमारी अनेकानेक जबर्दस्त विफलताओं तथा ग़लतियों के साथ प्राप्त हुई। और विफलताओं तथा ग़लतियों के बिना एक पिछड़ी हुई जनता क्या पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली तथा सबसे अग्रगामी देशों के साम्राज्यवादी युद्धों पर विजय पाने में सफल हो पाती। हम अपनी ग़लतियां स्वीकार करने से नहीं डरते और उन पर कड़ी नज़र दौड़ायेंगे ताकि उन्हें सुधारना सीखें। परन्तु तथ्य तो तथ्य बना रहता है: सैकड़ों-हज़ारों वर्षों में पहली बार दास-स्वामियों के बीच युद्ध का "उत्तर" समस्त तथा हर किस्म के दास-स्वामियों **के विरुद्ध** दासों की क्रान्ति द्वारा देने के वचन की अंतिम रूप से पूर्ति हो गयी तथा समस्त कठिनाइयों के बावजूद उसकी पूर्ति की जा रही है। ... **(अक्टूबर क्रान्ति की चौथी जयन्ती पर भाषण)**

* रूसी भाषा में "मीर" शब्द के दो अर्थ हैं: "शांति-संधि" और "संसार।" पुराने रूसी वर्ण-विन्यास के अनुसार इसे अलग-अलग ढंग से लिखा जाता था। – सं.

** दूसरा एवं ढाइवां इण्टरनेशनल – नकली कम्यूनिस्टों का इण्टरनेशनल।

हम भला क्यों साक्षर बनें?

(साक्षरता के नाम पर देश भर में अरबों रुपये फूंके जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी से पहले ही मुंह मोड़ लिया था। तमाम गैर सरकारी/स्वयंसेवी संगठन साक्षरता के नाम पर अपना नाम लिखना या दो-चार वाक्य पढ़ना सिखाकर आंकड़ों में साक्षरता की दरें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर आम जन खोखली व नकारा साक्षरता नहीं चाहते। वे ऐसी साक्षरता चाहतेहैं जो उनके जीवन की लड़ाई में उनके लिए हथियार का काम कर सके। लेकिन शासक वर्ग कभी ऐसी शिक्षा उनतक नहीं पहुंचने देगा। यह कविता पश्चिम बंगाल के गरीब और अशिक्षित लोगों के एक समूह से मिल कर तैयार की थी जिसे बंगाल सोशल सर्विस लीग ने कागज पर उतार कर सबसे पहले बांग्ला में प्रकाशित किया।)

हम किस तरह के लोग हैं?
हम हैं गरीब, बेहद गरीब
लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं
इसीलिए अनपढ़ होने के बावजूद
हम जिन्दा हैं
लेकिन हम जानना चाहते हैं
कि हम क्यों साक्षर बनें।

हम पहले भी साक्षरता की
कक्षाओं में गये,
लेकिन कुछ समय बाद, हमें
समझ आ गई।
हमें अपने साथ धोखा होता हुआ
लगा।
इसलिए हमने कक्षा छोड़ दी।

आपको मालूम, हमें क्या पता
चला?
कि बाबू लोग ये काम अपने ही

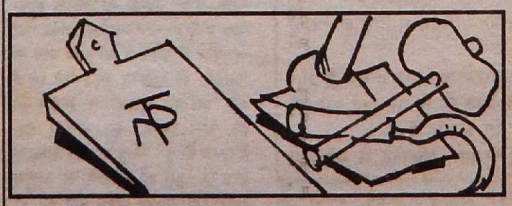

फायदे के लिए करते हैं।

शायद जल्दी ही चुनाव होने
वाले हैं,
या फिर कोई सरकारी पैसा या
कोई और चीज है जिसे खपाया
जाना है।
पर हमें जो पढ़ाया गया, वह
बेकार था।
अपना नाम भर लिख लेने से
क्या होगा
या कुछ शब्द पढ़ लेने से क्या
मिलेगा।

हम कक्षाओं में आने के लिए
तैयार हैं
बशर्ते तुम हमें सिखाओ
कि कैसे दूसरों पर निर्भर न रहा
जाये।
हम सीधी-सादी किताबें पढ़ सकें।
अपना हिसाब-किताब रख सकें,
चिट्ठी लिख सकें
और अखबारों को पढ़ और समझ
सकें
एक और चीज...
हमारे शिक्षक खुद को इतना
ऊंचा क्यों समझते हैं?
वे ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम
निरे बेवकूफ हों
जैसे हम छोटे बच्चे हों।
शिक्षक ऐसी चीजें जानते हैं, जो
हम नहीं जानते
लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीजें
जानते हैं
जो उनकी समझ से परे हैं।

हम खाली घड़े नहीं हैं
हमारे पास अपना दिमाग है
हम चीजों को तर्क से समझ
सकते हैं
और मानो या न मानो
हमारे पास आत्मसम्मान भी है।
जो हमें पढ़ाते हैं उन्हें यह याद
रखना चाहिए।
हमारे पास पहले ही मुश्किलों
और दुखों की कमी नहीं है
तुम्हारी कक्षाओं में जाकर हम
क्यों उन्हें बढ़ायें?

अगर शिक्षा के केन्द्र हमारी
जिन्दगी में
थोड़ी खुशी भर सकें
तो शायद हम कक्षाओं में जाने
की ललक अनुभव करेंगे।
हम बच्चे नहीं हैं
शिक्षक को यह याद रखना
चाहिए
हमसे बड़ों सा व्यवहार करें,
दोस्तों सा बर्ताव करें।

और हां! कुछ और बातें
हमें भरपेट खाना नहीं मिलता
हमारे पास पूरे कपड़े नहीं हैं
सर पर ठीक से छत भी नहीं है
ऊपर से हर साल बाढ़ सबकुछ
बहा ले जाती है
फिर आती है लम्बे सूखे की
बारी
सब कुछ सूख जाता है,
क्या तुम्हारी साक्षरता इसमें हमारे
काम आएगी?
क्या साक्षरता हमारी कठिन
जिन्दगी को थोड़ा बेहतर
बनाएगी? हमारी भुखमरी को
कम करेगी?
क्या इससे ये गारण्टी होगी
कि मां-बेटी दोनों को
एक ही साड़ी से काम चलाना
होगा
क्या इससे हमारे सिरों पर नया
छप्पर पड़ जायेगा?
वो कहते हैं कि हमें बचाने के
लिए और
हमारे लाभ के लिए
कानून बने हुए हैं
हम इन कानूनों को नहीं जानते
हमें अंधेरे में रखा जाता है
क्या तुम्हारी साक्षरता हमें इन
कानूनों को जानने में मदद देगी?
हम सीधा जवाब चाहते हैं

क्या हमें बेहतर बीज, खाद
और जरूरतभर का पानी
मिलेगा?
क्या हमें सही मजदूरी मिलेगी?
हम सोचते हैं ये सब जिन्दा
रहने के लिए जरूरी शिक्षाएं
हैं।
वो कहते हैं कि नये कार्यक्रम
में
ऐसी बातों का वादा किया
गया है
लेकिन क्या ये सिर्फ कागज के
टुकड़े पर लिखी इबारत भर है?
क्या ये अतीत के उन डेरों वादों
की तरह है
जो कभी पूरे नहीं होते

क्या यह कार्यक्रम हमें मिलकर
सोचना और काम करना
सिखाएगा?
क्या 'करना' भी 'सीखने' का
एक अंग होगा?
अगर यह सब किया जाता है,
तो हम सब साक्षरता की कक्षाओं
में आयेंगे।
तब यह शिक्षा जिन्दगी को बेहतर
बनाने की शिक्षा होगी।

हम कमजोर हैं
और अक्सर बीमार रहते हैं
क्या यह कार्यक्रम
हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान
रखना
और मजबूत बनना सिखायेगा
अगर ये ऐसा करेगा, तो हम सब
आयेंगे

फिर हम तय करेंगे
कि हमें साक्षर बनना चाहिए या
नहीं
लेकिन अगर हमें पता चला
कि हमें फिर छला जा रहा है
झूठे वादों से
तो हम तुमसे दूर रहेंगे
हम कहेंगे,
'भगवान के लिए, हमें अकेला
छोड़ दो।'

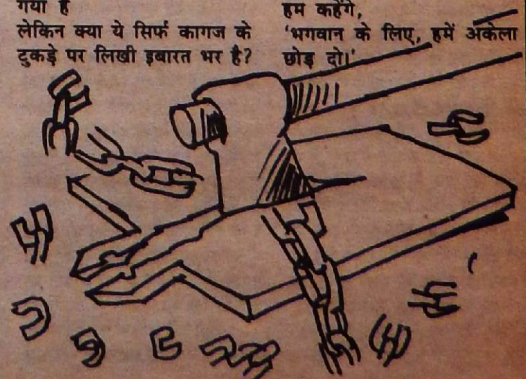

अब तक का सबसे जनविरोधी काला कानूनपोटो

(पेज 1 से आगे)

रासायनिक या जैविक हथियारों जैसी चीज़ों के साथ "किसी भी अन्य तरीके से" को भी जोड़ा गया है। कहने की जरूरत नहीं कि यह "किसी भी अन्य तरीके से" इतना ख़तरनाक है कि इसके दायरे में किसी भी किस्म के विरोध, निजी या सार्वजनिक, हिंसक या अहिंसक गतिविधि की मंशा आतंकवादी ठहरायी जा सकती है।

इस मंशा का फैसला करने का अधिकार भी पुलिस को सौंप दिया जा सकता है। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि सरकार के किसी भी कदम के खिलाफ पर्चा बांटना, सभा करना, जुलूस-रैली निकालना, लेख लिखना, गीत गाना, या किसी खास समय पर किसी खास जगह मौजूद रहना ही पोटो के दायरे में लाये जाने के लिए काफी होगा। पोटो जारी होने के पहले ही अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले के विरोध में दिल्ली में पर्चा बांट रहे छह छात्रों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार करके सरकार ने साफ तौर पर अपनी मंशा का सुराग दे दिया है।

पोटो के प्रावधान यूं तो जनता के हर तबके के लिए ख़तरनाक है लेकिन देश की मेहनतकश आबादी के लिए ये खास तौर पर ख़तरनाक है। अब निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधतंत्र के जोरो-जुल्म के ख़िलाफ वाजिब हकों के लिए होने वाले मज़दूरों के किसी भी संघर्ष को "सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने" या आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाली कार्रवाई मानकर उसे आतंकवादी कार्रवाई घोषित किया जा सकता है। सरकारी कारखानों या दफ्तरों के कर्मचारियों की गर्दन पर 'आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम' (एस्मा) की तलवार पहले ही लटकती रहती थी, जिसके कारण अपने वाजिब हकों के लिए भी हड़ताल पर गये कर्मचारी भयभीत रहा करते थे। अब पोटो लागू होने के बाद सरकार के किसी भी कर्मचारी विरोधी या दमनकारी कदम के विरोध में खड़ा होने के लिए पोटो के आतंक से भी बाहर आने की कशमकश करनी होगी। दरअसल, देश की सरकार यह मानती है कि देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा ख़तरा देश की जनता से है, इसलिए उसे कुचल डालो।

सरकार द्वारा पोटो के समर्थन में किये जा रहे प्रचार से जिन्हें यह भ्रम हो कि इस कानून का इस्तेमाल डब्ल्यू. टी. ओ. के खिलाफ प्रदर्शनरत किसानों, छंटनी-तालाबन्दी के खिलाफ आन्दोलनरत मज़दूरों, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते छात्रों-नौजवानों,अल्पसंख्यकों, ईमानदार- जुझारू पत्रकारों, वकीलों, शिक्षकों, कलाकारों, जनतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं किया जायेगा, उन्हें टाडा के तहत बन्द किये गये लोगों की सूची देख लेनी चाहिए। टाडा के तहत देश भर में कुल 76000 लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था जिसमें महज एक प्रतिशत लोगों को ही सजा हुई थी। हज़ारों बेगुनाह बिना मुकदमा चले ही बारह-बारह सालों तक जेलों में सड़ते रहे। टाडा खत्म हो जाने के छह साल बाद भी क़रीब पन्द्रह हज़ार लोग सलाखों के पीछे क़ैद हैं।

पोटो कई मामलों में टाडा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके तहत पुलिस हिरासत की अवधि पन्द्रह दिन से बढ़ाकर तीस दिन तक कर दी गयी है। इतना ही नहीं पुलिस अधिकारी के सामने दिये गये इकबालिया बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा। न्यायिक हिरासत में लिये जाने के बाद भी अगर पुलिस चाहे तो पूछताछ के लिए दुबारा पुलिस रिमाण्ड में ले सकती है। इस तरह किसी अभियुक्त को कुल मिलाकर छह माह की अवधि तक पुलिस रिमाण्ड में रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब केन्द्र सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार से इसकी इजाजत मिले और वह भी पोटो के विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के सिर्फ तीस दिन के भीतर ही। पोटो अभियुक्त को अग्रिम जमानत मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता उसे जमानत भी सिर्फ तभी मिल सकती है जब न्यायालय को अभियुक्त की बेगुनाही का विश्वास हो जाये। यह कानून अदालत को यह अधिकार देता है कि वह बिल्कुल पुख्ता सबूत के बिना महज संदेह या विश्वास के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराकर सजाए-मौत तक दे सकती है। इतना ही नहीं गवाहों को धमकियों और डराये जाने से बचाने की आड़ लेकर जिरह के समय गवाहों की पहचान गुप्त रखी जायेगी और सुनवाई बन्द कमरे में की जायेगी। यानी पुलिस का काम बेहद आसान – न सबूत जुटाने की जरूरत, न तहकीकात के समय चाक-चौबन्द रहने की जरूरत और फर्जी गवाह खड़े कर झूठे केस बनाने की कला में भला भारतीय पुलिस का मुकाबला कौन कर सकता है।

बिल्कुल साफ है कि इस कानून ने पुलिस के हाथों में बेलगाम अधिकार सौंप दिये हैं। उस पुलिस के हाथों में – जो फर्जी मुकदमें ठोंकने, नकली गवाह तैयार करने, सबूत नष्ट करने, अपराधियों को संरक्षण देने, पुलिस हिरासत में बर्बर यातनाएं देने, फर्जी मुठभेड़ें दिखाने और हर साल हिरासत में सैकड़ों लोगों को मार डालने के लिए कुख्यात है। उस पुलिस के हाथों जिसे देश के एक सम्मानित न्यायाधीश ने कुछ सालों पहले सबसे संगठित गुण्डा गिरोह की संज्ञा दी थी।

यह साफ-साफ हमें चेतावनी दे रहा है कि किसी भी प्रकार का विरोध या असहमति नाजायज है। आतंकवादी कार्यों में सहयोग देने की परिभाषा का दायरा इतना व्यापक है कि मान लीजिए अगर कोई पत्रकार किसी प्रतिबंधित संगठन के नेता का साक्षात्कार लेता है तो वह इसके स्रोत के बारे में बताने के लिए बाध्य है। मान लीजिए आप अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति से कोई सम्पत्ति खरीदते हैं जो किसी "आतंकवादी" की है तो वह सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी और अपको सजा भी हो सकती है। यहां तक कि आपने किसी ऐसी गोष्ठी में भाग लिया या महज उपस्थित रहे हों जिसमें कोई वक्ता कश्मीर में जनमत संग्रह कराये जाने के पक्ष में बोल रहा हो तो सिर्फ उपस्थित होने के कारण ही आप इस कानून की चपेट में आ जायेंगे।

लेकिन इस कानून के प्रावधानों के बारे में गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, कानून मंत्री अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण शोरी से लेकर भाजपा के सभी-मंत्री-नेता मीडिया के सहारे इसके पक्ष में जनमत तैयार करने के मकसद से लगातार सफेद झूठ बयान कर रहे हैं। यह बेहया कुतर्क दिया जा रहा है कि जो पोटो का विरोधी है वह राष्ट्रविरोधी और आतंकवाद समर्थक है और चिन्ता की बात यह है कि मध्यवर्ग का एक अच्छा-खासा पढ़ा-लिखा हिस्सा इस कुप्रचार से प्रभावित भी हो रहा है। इसलिए, आज जरूरत इस बात की है कि किसी अन्धी राष्ट्रभक्ति की भावना में बहकर भाजपाई कुप्रचार में बहने के बजाय विवेकसम्मत ढंग से सरकार की कुत्सित मंशा को समझने की जरूरत है।

पोटो लागू करने के पीछे आतंकवाद से निपटना तो सिर्फ बहाना है। दरअसल असली निशाना तो जनता है। सरकार वर्तमान से नहीं भविष्य के ख़तरे से ज़्यादा घबरायी हुई है। जनविरोधी आर्थिक नीतियों के कारण समाज में बढ़ती तबाही बर्बादी ने सत्ताधारियों के सामने गम्भीर राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। पिछले दस वर्षों से जारी निजीकरण व "उदारीकरण" की नीतियों से लोगों को मिली नौकरियां भी छिनती जा रही हैं। बेरोजगारों की पूरी फौज खड़ी हो चुकी है। शिक्षा-चिकित्सा जैसी बुनियादी सहूलियतें भी अब अमीरों की बपौती बन चुकी है। अमीरी-ग़रीबी की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नफ़रत भी तीखी होती जा रही है। संक्षेप में कहें तो पूरा समाज आज ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है और जनअसंतोष का लावा सतह के नीचे खदबदा रहा है। आने वाले व्यापक जनविरोधों का वह खौफ ही है जो सत्ताधारियों के दिलों में समाया हुआ है। इसीलिए जनता को कुचलने और डराने के लिए हर तरह के हथियारों से वे खुद को लैस कर लेना चाहते हैं। पोटो ऐसा ही एक हथियार है।

यह सही है कि शासक वर्गों की तमाम राजनीतिक पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी (जो संघ परिवार की राजनीतिक शाखा है) की विचारधारा ज़्यादा निरंकुश स्वेच्छाचारी है और वह अपने आक्रामक हिन्दुवादी फासीवादी एजेण्डे को आगे बढ़ाने के लिए इस कानून का भरपूर उपयोग करेगी, लेकिन यह मानना भ्रम होगा कि अन्य विपक्षी पार्टियां सचमुच इसकी विरोधी हैं। जिन हालात में देश के भीतर 26 जून 1975 में आपात काल लागू हुआ था उन हालात को हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें यह भी याद कर लेना चाहिए कि यह कांग्रेसी शासन में हुआ था। आज हालात उस समय से कई गुना अधिक विस्फोटक होते जा रहे हैं और इसलिए आज शासक वर्गों के लिए दमन के हरबा-हथियारों से लैस होना उस समय से अधिक जरूरी हो गया है।

पूंजीवादी सत्ताधारियों के लिए यह पहला झटका था जिसे वे संभाल नहीं सके थे। उस वक्त तक शासक वर्ग भी एकमत नहीं था और उसका एक बड़ा हिस्सा आपातकाल का विरोधी बन गया था। उसके बाद भारतीय शासक वर्ग ने इससे सीख ली, अब वे और माहिर और कुशल हुए हैं। उन्होंने यह सबक निकाला है कि बिना आपातकाल लगाये "जनतंत्र" का बाना ओढ़कर ख़तरनाक काले कानूनों के माध्यम से जनता के न्यायसंगत आन्दोलनों को कैसे कुचला जाये। और इस मुद्दे पर आज पूंजीपति शासक वर्गों की सेवा में जुटी हर राजनीतिक पार्टी आज अन्दरखाने में एकमत है। तात्कालिक चुनावी स्वार्थों के नात आज विपक्ष की कुछ पार्टियां भले ही हो-हल्ला मचा लें लेकिन मौजूदा पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूटतंत्र की हिफाजत के दूरगामी मुद्दे पर उनके बीच आज पक्की एकता है।

हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि देशभर में व्यापक जनविरोध के कारण तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने 1995 में टाडा कानून तो वापस ले लिया था लेकिन उसी वक्त 'क्रिमिनल ला अमेंडमेंट बिल' नाम से उसी कानून का नया संस्करण लाने की कोशिश की थी, जिसे उस समय पास नहीं कराया जा सका था। उसके बाद अलग-अलग रूपों में भी ऐसे प्रयास हुए। तमिलनाडु सरकार ने 'पोटा' नाम का कानून लागू किया तो आन्ध्रप्रदेश में भी इसी तर्ज पर कानून लागू करने का प्रयास हुआ। अप्रैल 1999 में 'महाराष्ट्र कंट्रोल आफ आर्गनाइज्ड क्राइम ऐक्ट' (मोक्का) लागू किया है। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने भी संगठित अपराधों को रोकने के नाम पर 'टाडा' जैसा कानून थोपने की कोशिश की थी लेकिन घटक दलों के विरोध के कारण यह कोशिश तात्कालिक रूप से असफल हो गयी। कहने का अर्थ यह कि आज जो पार्टियां पोटो का विरोध करने का दम भर रही हैं चाहे वे संसदीय वामपंथी पार्टियां ही क्यों न हो, वे सिर्फ अपनी किन्हीं फौरी राजनीतिक मजबूरियों के चलते ही कर रही हैं। चूंकि सबके दामन दागदार हैं और मंशा एक, इसीलिए भाजपा के नेताओं को उन पर उंगली उठाने और 'आतंकवाद की मदद करने' की तोहमत लगाने का मौका भी मिल रहा है। जयललिता ने तो खुलेआम 'पोटो' को समर्थन दिया है।

हो सकता है कि अलग-अलग राजनीतिक मजबूरियों के चलते संसद के इस सत्र में विरोधी पार्टियां पोटो पर मुहर न लगने दें, लेकिन इससे भी ख़तरा सिर्फ कुछ समय के लिए टलेगा। फिर मौका ताड़कर इसे थोपने की कोशिश की जायेगी। वैसे और नहीं तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो सुरक्षित ही है। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सवाल पर जिस तरह मतभेद है उसे देखकर और कांग्रेस के चरित्र को देखते हुए यह भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वह संसद में 'पोटो' का विरोध करेगी ही।

ऐसे में हमें बिना किसी भ्रम में अपनी शक्ति पर ही सबसे अधिक भरोसा करने की जरूरत है। मेहनतकशों की मजबूत गोलबन्दी और सभी जनतांत्रिक शक्तियों की व्यापक एकजुटता के दम पर ही 'पोटो' के राक्षस का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए 'पोटो' के खिलाफ हर जगहों पर व्यापक रूप से गोलबन्दी होनी चाहिए, इसे दफ़न करने के लिए संघर्ष होना चाहिए।

हालांकि 'पोटो' के खिलाफ प्रगतिशील जनतांत्रिक ताकतों के भीतर सुगबुगाहट मौजूद है लेकिन हमें यह समझना होगा कि 'पोटो' को वापस लेने पर मजबूर करने के लिए जगह-जगह सड़कों पर उतरना होगा। कुछ प्रगतिशील-जनपक्षधर व्यक्ति पोटो के दायरे में पत्रकारों को लाये जाने के खिलाफ ही आक्रोश प्रकट करे रहे हैं और 'प्रेस की आज़ादी' के सवाल को ही 'पोटो-विरोध' का केन्द्रीय मुद्दा बना रहे हैं। इन लोगों को यह समझना होगा कि 'प्रेस की आज़ादी पर' अंकुश लगाने का सवाल अहम होते हुए भी पोटो के अन्य ख़तरनाक प्रावधानों का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। इसलिए हमें टुकड़ों में नहीं बल्कि जनता को कुचलने-डराने-धमकाने के एक ख़तरनाक हथियार के रूप में 'पोटा' के समूचे दस्तावेज का इस समूचे अध्यादेश का ही विरोध करना होगा। बात सिर्फ यह भी नहीं है कि 'पोटो' के प्रावधानों का दुरूपयोग होगा, असली बात यह है कि इसका दुरुपयोग करने के लिए ही इसे जारी किया गया है। जिस कानून का निशाना ही जनता हो उसके दुरुपयोग-सदुपयोग की बहस ही बेमानी है। पोटो के दानव को सिर्फ दफ़न किया जाना चाहिए क्योंकि शरीफ दानव जैसी कोई चीज़ नहीं होती।

14 नवम्बर, 2001

क्या आप आतंकवादी हैं?

इस नये कानून के तहत आप भी आतंकवादी करार दिये जा सकते हैं। अगर...

- एक पत्रकार, जो किसी प्रतिबंधित संगठन के नेता का साक्षात्कार लेने के बाद स्रोत बताने से इनकार करे।
- एक व्यक्ति, जो सरकार के किसी अप्रिय कदम को वापस लिये जाने की मांग के समर्थन में पर्चे बांट रहा हो।
- एक फिल्मकार, जो जेलों और जेलों के हालात पर बनायी जा रही श्रृंखला के हिस्से के रूप में टाडा बन्दियों की दयनीय स्थिति पर फिल्म बनाये।
- रेलवे कर्मचारी, जो रेल विभागों के निजीकरण की कोशिश के खिलाफ काम रोके।
- हड़ताली सरकारी कर्मचारी, जो किसी कर्मचारी को हड़ताल तोड़ने से जबरदस्ती रोकने की कोशिश करें।
- एक पुस्तक विक्रेता, जो ऐसी किताबें रखे जिसमें लोगों की राष्ट्रीयता की आकांक्षा के पक्ष में बात की गयी हो।
- एक वकील, जो किसी प्रतिबंधित संगठन के तथाकथित सदस्यों के बचाव के लिए पैरवी करें।
- कोई व्यक्ति, जो उस गोष्ठी में उपस्थित हो या उस गोष्ठी में मंच पर आये जिसमें कोई एक वक्ता कश्मीर में जनमत संग्रह करवाये जाने के पक्ष में बोले।
- एक टेलीविजन समाचार चैनल, जो उत्तर-पूर्व में सेना की ज्यादतियों के विरोध में देश के किसी भी भाग में हो रहे प्रदर्शन को चित्रित करे।
- टेलीविजन का एक बातचीत का कार्यक्रम, जिसमें अशान्त सीमान्त क्षेत्रों के द्वन्द्वों पर विचार विमर्श के दौरान एक ऐसा मत व्यक्त होने दिया जाए जिसमें अलगाववादी आन्दोलन के साथ सहानुभूति प्रकट की गयी हो।
- एक व्यक्ति जो यह 'भविष्यवाणी' करे कि किसी विशिष्ट राजनीतिक दल की किन्हीं अप्रिय नीतियों के कारण उसके नेताओं पर हमले हो सकते हैं।
- एक यात्री, जिसकी उंगलियों के निशान उस बस से मिले हों जिसमें बम विस्फोट हुआ था।

अगर आप किसी कारण से सत्ताधारियों को नाराज कर दें और ऊपर दी गयी किसी भी श्रेणी में आते हों तो आपको इस नये कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।!

(पी.यू.डी.आर. बुकलेट से साभार)

लेनिन के साथ दस महीने

एल्बर्ट रीस विलियम्स उन पांच अमेरिकी जनों में से एक थे जो अक्टूबर क्रान्ति के तूफानी दिनों के साक्षी थे। वे 1917 के वसंत में रूस पहुंचे। उस समय से लेकर अक्टूबर क्रान्ति तक, वे तूफान के साक्षी ही नहीं बल्कि भागीदार भी रहे। इस दौरान उन्होंने व्यापक जनता के शौर्य एवं सृजनशीलता के साथ ही बोल्शेविक योद्धाओं के जीवन को भी निकट से देखा। लम्बे समय तक वे लेनिन के साथ-साथ रहे। क्रान्ति के बाद जुलाई, 1918 तक उन्होंने दुनिया भर की प्रतिक्रियावादी ताकतों से जूझती पहली सर्वहारा सत्ता के जीवन-संघर्ष को निकट से देखा।

स्वदेश लौटकर रीस विलियम्स ने दो किताबें लिखीं – 'लेनिन: व्यक्ति और उनके कार्य' तथा 'रूसी क्रान्ति के दौरान'। ये दोनों पुस्तकें एक जिल्द में 'अक्टूबर क्रान्ति और लेनिन' नाम से राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी हैं।

हम रीस विलियम्स की पूर्वोक्त पहली पुस्तक का एक हिस्सा 'बिगुल' के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

– संपादक

(पिछले अंक से आगे)

9. लेनिन का असाधारण आत्मनियंत्रण

लेनिन सभी अवसरों पर पूर्ण आत्मनियंत्रण कायम रखते थे। जिन घटनाओं से अन्य लोग बहुत आवेश में आ जाते, उस परिस्थिति में भी वे शान्त रहते और धैर्य का परिचय देते।

संविधान सभा* के एक ऐतिहासिक अधिवेशन में उसके दो गुट एक-दूसरे का गला काटने को तैयार थे और इससे कोलाहलपूर्ण वातावरण पैदा हो गया था। प्रतिनिधि चीख-चिल्ला रहे थे और अपनी मेजों को पीट रहे थे, वक्ता उच्चतम स्वरों में धमकियां और चुनौतियां दे रहे थे और दो हज़ार प्रतिनिधि जोश और आवेश में अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी अभियान-सम्बन्धी गान गा रहे थे। वातावरण बहुत ही उत्तेजनापूर्ण हो गया था। ज्यों-ज्यों रात गुजरती गई, त्यों-त्यों उत्तेजना और बढ़ती गई। दर्शक दीर्घाओं में हम लोग रेलिंग को कसकर पकड़े हुए थे, तनाव से होंठ भिंचे हुए थे। हमारा धैर्य जवाब देने वाला था। पहली पंक्ति के बाक्स में बैठे हुए लेनिन ऊबे-से दिखाई पड़ रहे थे।

अन्त में वे अपनी जगह से उठे और मंच के पीछे जाकर लाल गलीचे से आच्छादित सीढ़ियों पर बैठ गये। जब-तब वे प्रतिनिधियों के समूह पर दृष्टि डाल लेते। उस समय ऐसा प्रतीत होता जैसे वे कह रहे हों, "यहां इतने व्यक्ति अपनी स्नायविक शक्ति यूं ही नष्ट कर रहे हैं। पर खैर, यहां एक व्यक्ति है, जो उसका संचय करने जा रहा है।" अपनी हथेलियों पर सिर रखकर वे सो गये। वक्ताओं का वक्तृत्व-कौशल और श्रोताओं की चिल्लाहट उनके सर पर गूंजती रही, परन्तु वे शान्तिपूर्वक ऊंघते रहे। एक या दो बार उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, पल भर को इधर-उधर देखा और फिर सो गये।

अन्तत: वे उठे, अंगड़ाई ली और धीरे-धीरे पहली पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर बैठ गये। उचित अवसर देखकर रीड और मैं सांविधान सभा की कार्यवाही के बारे में प्रश्न पूछने के लिए उनके पास चले गये। उन्होंने अन्यमनस्क भाव से उत्तर दिये। उन्होंने प्रचार कार्यालय** के कार्यकलाप के बारे में पूछा। जब हमने उन्हें बताया कि काफी सामग्री मुद्रित हो रही है और जर्मन फौजों की खाइयों में पहुंच रही है, तो प्रसन्नता से उनका चेहरा चमक उठा। मगर जर्मन भाषा में सामग्री तैयार करने में हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

बख़्तरबन्द गाड़ी पर मेरे कारनामे को स्मरण कर उन्होंने अचानक प्रफुल्ल मुद्रा में कहा, "कहये, रूसी भाषा की पढ़ाई का क्या हालचाल है? अब तो इन सभी भाषणों को समझ लेते हैं न?"

मैंने बात टालते हुए उत्तर दिया, "रूसी भाषा में इतने अधिक शब्द हैं।" उन्होंने तुरन्त प्रत्युत्तर देते हुए कहा, "यही तो बात है, आपको रूसी भाषा का विधिवत् अध्ययन करना चाहिए। शुरू में ही उसकी कमर तोड़ डालनी चाहिए। इस बारे में मैं आपको अपना तरीका बताता हूं।"

यथार्थ में लेनिन की प्रणाली इस प्रकार की थी: सबसे पहले सभी संज्ञाओं, क्रियाओं, क्रिया-विशेषणों और विशेषणों को याद कर जाओ, शेष सभी शब्दों को याद कर लो, व्याकरण को कंठस्थ कर लो, वाक्य-रचना का ज्ञान प्राप्त कर लो और इसके बाद हर जगह और हर किसी से बातचीत करते हुए इसका अभ्यास करो। स्पष्ट है कि लेनिन की प्रणाली सूक्ष्म न होकर, पक्की और गहन थी। संक्षेप में पूंजीवाद पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस प्रणाली को अपनाया था, भाषा पर विजय प्राप्त करने की उनकी प्रणाली भी वैसी ही थी अर्थात जी-जान से अपने कार्य में जुट जाओ। परन्तु इस प्रणाली में वे काफी हाथ मांज चुके थे।

लेनिन बाक्स पर झुके हुए थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और संकेतों से अपने शब्दों के अभिप्राय स्पष्ट कर रहे थे। हमारे सहयोगी अन्य संवाददाता – बड़ी ईर्ष्या के साथ देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि लेनिन खूब जोर-शोर से विरोधी पक्ष के अपराधों का पर्दाफाश कर रहे हैं, अथवा सोवियतों की गुप्त योजनाएं प्रकट कर रहे हैं या हममें क्रोतिकारी भावनाएं भर रहे हैं। इस प्रकार के संकट में निश्चय ही महान रूसी राज्य के प्रधान से ऐसे ही विषय पर सशक्त अभिव्यक्ति की आशा की जा सकती थी। परन्तु संवाददाताओं का अनुमान ग़लत था। उस समय रूस के प्रधान मंत्री केवल यह बता रहे थे कि किसी विदेशी भाषा का ज्ञान कैस प्राप्त करना चाहिए और उस संक्षिप्त मैत्रीपूर्ण वार्तालाप द्वारा थोड़ी देर के लिए वहां के वातावरण से मुक्त होकर अपना मनोरंजन कर रहे थे।

बड़ी-बड़ी बहसों के तनावपूर्ण वातावरण में, जब उनके विरोधी बहुत ही निर्ममता के साथ उनकी आलोचना किया करते थे, उस समय भी लेनिन अनुद्विग्न बैठे रहते और यहां तक कि उस स्थिति में भी हास-परिहास द्वारा अपना मनोरंजन कर लेते। सोवियतों की चौथी कांग्रेस में अपना भाषण समाप्त करने के बाद अपने पांच विरोधियों की आलोचनाओं को सुनने के लिए वे मंच पर ही बैठ गये। जब भी उन्हें यह आभास होता कि विरोधी ने कोई उचित बात कही है, तो लेनिन खुलकर मुस्कराते और हर्षध्वनि में शामिल होते। जब भी वे समझते कि हास्यास्पद और बेसिर-पैर की बात कही गई है, तो लेनिन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कराते, खिल्ली उड़ाने की भावना से अंगूठों को सटाये हुए ताली बजाते।

10. लेनिन व्यक्तिगत बातचीत में

मैंने केवल एक बार ही लेनिन को थका-हारा देखा। जन-कमिसार परिषद् की आधी रात तक चलने वाली बैठक के बाद वे 'नेशनल' होटल में अपनी पत्नी और बहन के साथ लिफ्ट में कदम रख रहे थे। परिश्रान्त स्वर में उन्होंने अंग्रेजी में कहा, "गुड ईवनिंग।" फिर अपनी भूल सुधारते हुए बोले, "इट इज गुड मार्निंग। मैं सारा दिन और रात को भी बातचीत करता रहा हूं और थक गया हूं। यद्यपि एक ही मंजिल ऊपर चढ़ना है, फिर भी मैं लिफ्ट से जा रहा हूं।"

मैंने केवल एक ही बार उन्हें जल्दी-जल्दी अथवा झपटते हुए आते देखा। यह फरवरी की बात है, जब ताव्रीचेस्की प्रासाद फिर से तीखी नोकझोंक – जर्मनी के साथ युद्ध या शान्ति के प्रश्न की बहस – का केन्द्र बना हुआ था।

वे तेजी से लम्बे डग भरते और प्रवेश-कक्ष को लांघते हुए सभा-मंच द्वार की ओर बढ़े जा रहे थे। प्रोफेसर चार्ल्स कूंत्स तथा मैं वहां खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने उनका अभिवादन करते हुए कहा, "कामरेड लेनिन, जरा रुकिये तो एक मिनट।"

उन्होंने तेजी से बढ़ते हुए अपने कदमों को रोक लिया और लगभग एक फौजी की भांति सावधान खड़े होते हुए गंभीरतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, "साथियो, कृपया इस समय मुझे मत रोकिये। मेरे पास एक सेकेण्ड का भी समय नहीं है। वे हाल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया, इस समय मुझे क्षमा करें, मैं रुक नहीं सकता।" उन्होंने फिर से सिर झुकाया, हम दोनों से हाथ मिलाया और पुन: तेजी से आगे बढ़ गये।

बोल्शेविक-विरोधी विलकाक्स ने लोगों के साथ लेनिन के मधुर व्यवहार पर अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि एक अंग्रेज सौदागर एक नाजुक स्थिति में अपने परिवार की रक्षा के उद्देश्य से लेनिन की निजी सहायता प्राप्त करने के लिए उनके पास गया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि "रक्त का प्यासा क्रूर शासक" मृदुस्वभाव का, शालीन व्यक्ति है, उसका बर्ताव सहानुभूतिपूर्ण है और वह अपनी शक्ति भर सभी सहायता प्रदान करने को प्राय: उत्सुक है।

सचमुच कभी-कभी वे हद से अधिक अतिरंजित रूप में शालीनता और विनम्रता प्रकट करते थे। हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण ऐसा होता रहा हो – वे पुस्तकों से प्राप्त शिष्ट बातचीत के परिष्कृत रूपों का पूर्णतया प्रयोग करते रहे हों। लेकिन इस बात की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है कि यह उनके सामाजिक आचार-व्यवहार के ढंग का अभिन्न अंग हो, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की भांति लेनिन सामाजिक शिष्टाचार में भी बहुत ही दक्ष थे। वे गैरमहत्वपूर्ण व्यक्तियों से बातचीत में अपना समय नष्ट नहीं करते थे। आसानी से उनसे भेंट नहीं हो सकती थी। उनके भेंट-कक्ष में यह सूचना-पत्र लगा हुआ था:

"मुलाकातियों से यह ध्यान में रखने को कहा जाता है कि उन्हें ऐसे व्यक्ति से बातचीत करनी है, जो काम की अधिकता के कारण बहुत ही व्यस्त रहता है। अनुरोध है कि भेंट करने वाले अपनी बात संक्षेप में साफ-साफ कहें।"

लेनिन से मिलना कठिन था, पर ऐसा हो जाने पर वे मुलाकाती की हर बात पर कान देते। उनका सारा ध्यान मुलाकाती पर ऐसे संकेन्द्रित हो जाता कि उसे घबराहट तक अनुभव होने लगती। विनम्र एवं प्राय: भावात्मक अभिवादन के पश्चात वे भेंट करने वाले के इतने निकट आ जाते कि उनका चेहरा एक फुट से भी कम दूरी पर रह जाता। बातचीत के दौरान वे और भी सटते चले जाते और भेंटकर्त्ता की आंखों में ऐसे टकटकी लगाकर देखते मानो उसके मस्तिष्क के अन्तस्तल की थाह ले रहे हों, उसकी आत्मा में झांक रहे हों। केवल मलिनोव्स्की जैसा निर्लज्ज झूठा व्यक्ति ही ऐसी पैनी निगाह के दृढ़ प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता था।

एक ऐसे समाजवादी से हम लोग अक्सर मिला करते थे, जिसने 1905 में मास्को की क्रान्ति में भाग लिया था और जो मोर्चेबन्दी पर भी जमकर लड़ चुका था। सुख और आराम का जीवन व्यतीत करने तथा व्यक्तिगत सफलता एवं उन्नति की भावना से वह अपनी प्रथम ज्वलन्त निष्ठा से विचलित हो चुका था। वह अब अनेक पत्र-पत्रिकाओं को प्रकाशित करने वाली एक अंग्रेजी संस्था के पत्रों एवं प्लेखानोव*** के पत्र 'येदीन्स्त्वो' का संवाददाता था और खूब बना-ठना रहता था। पूंजीवादी लेखकों से भेंट करने को लेनिन अपना समय बर्बाद करना मानते थे; परन्तु इस व्यक्ति ने अपने पुराने क्रान्तिकारी कारनामों का उल्लेख कर लेनिन से मुलाकात का समय प्राप्त कर लिया था। जब वह उनसे भेंट करने जा रहा था, तो बहुत ही उत्साहपूर्ण मुद्रा में था। मैंने कुछ घंटे बाद उसे बहुत ही बेचैन देखा। उसने बताया:

"जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, तो मैंने 1905 की क्रान्ति में अपने कार्य का उल्लेख किया। लेनिन मेरे पास आकर बोले, 'हां, कामरेड, मगर इस क्रान्ति के लिए अब आप क्या कर रहे हैं?' उनका चेहरा मुझसे 6 इंच से अधिक दूरी पर नहीं था और उनकी आंखें एकटक मेरी आंखों की ओर देख रही थीं। मैंने मास्को में मोर्चेबन्दी के दिनों के अपने कार्यों की चर्चा की और एक कदम पीछे हट गया। परन्तु लेनिन एक कदम आगे बढ़ आये और मेरी आंखों में आंखें डाले हुए ही उन्होंने पुन: कहा, 'हां, कामरेड, मगर इस क्रान्ति के लिए अब आप क्या कर रहे हैं?' ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे मेरी आत्मा का एक्सरे कर रहे थे – मानो पिछले 10 वर्षों के मेरे सारे कारनामों को साफ-साफ देख रहे थे। मैं उनकी इस नज़र की ताब न ला सका। एक दोषी बालक की भांति मेरी नज़र झुक गई। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, मगर असफल रहा। मैं उनके सामने ठहर न सका और चला आया।" कुछ दिनों बाद इस व्यक्ति ने इस क्रान्ति में अपने को झोंक दिया और सोवियतों का कार्यकर्त्ता बन गया।

लखनऊ में शिशु संहार

असली हत्यारे हाथों की शिनाख्त ज़रूरी

(बिगुल प्रतिनिधि)

लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल कालेज में एक ही दिन में 12 नवजात शिशुओं की मौत की असली वजह क्या है? इसका जवाब न प्रधानमंत्री दफ्तर से भेजी गयी डाक्टरों की जांच टीम दे सकती है और न ही अन्य गठित तीन जांच टीमें। हो सकता है ये जांच टीमें कुछेक डाक्टरों या प्रशासनिक अफ़सरों पर लापरवाही के आरोप लगा दें और उन्हें थोड़ी बहुत सजाएं भी मिल जायें लेकिन यह तो वही रूटीन जांच होगी जैसा रिवाज है। हमें चिकित्सा जैसे सबसे मानवीय पेशे में सर्वव्यापी हो चुकी आम संवेदनहीनता की तहों तक जाना ही होगा तभी यह गारण्टी हो सकती है कि ऐसी मौतें न हों।

दरअसल किंग जार्ज मेडिकल कालेज में शिशुसंहार हुआ है – उस व्यवस्था के हाथों, जो युद्ध के दिनों में बर्बर नरसंहार रचती है और शान्ति के दिनों में अकाल, भुखमरी और भोपाल जैसी दुर्घटनाएं और रोज-रोज होने वाले उन अनगिनत लापरवाहियों का कारण बनती है जिसमें रोज-रोज अनगिनत ठंडी हत्याएं होती रहती हैं। लखनऊ में भी शान्ति के दिनों में ऐसा ही शिशु संहार हुआ है।

बाज़ार और मुनाफे का वह मानवभक्षी तंत्र, जिसमें पैसा आदमी की जान से अधिक प्यारा होता है, चिकित्सा जैसे मानवीय कहे जाने वाले पेशे को भला अपनी रंगत में ढालने में क्यों बख्शेगा। आज डाक्टरी की पढ़ाई कोई इसलिए नहीं करता कि इससे वह मानवता की सेवा करेगा। डाक्टरी आज तमाम स्वतंत्र पेशों में सबसे अधिक कमाऊ पेशों में से एक है। इसलिए एक बार डाक्टर बन जाने के बाद कुछेक अपवादों को छोड़कर आदमी की बीमारी से तिजोरियां भरने की होड़ मच जाती है। निजी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों, निजी अस्पतालों, दवा बनाने वाली कम्पनियों, पैथालोजी, जांच करने वाली दुकानों की सांठ-गांठ से पैसा कमाना, मुनाफा पीटना इसी होड़ की देन है। निजी डाक्टर के लिए मरीज एक ग्राहक मात्र होता है, जिसकी जेब पर डाका डालना उसका पावन कर्तव्य है। इन्सान की ज़िन्दगी और ग़रीब की बेबसी पर ध्यान देने की भला फुर्सत कहां।

जब लोगों की बीमारी से पैसा कमाने की होड़ मची हो तो फिर सरकारी डाक्टर या मेडिकल कालेज के डाक्टर रूखी-सूखी तनख्वाहों पर भला क्यों गुजारा करें। वे मेडिकल कालेज या सरकारी अस्पताल जाते तो हैं, लेकिन इसलिए कि अपनी निजी प्रैक्टिस या नर्सिंग होम के लिए मरीज फंसा सकें, ऐसे में यह देखने की फुर्सत कहां कि वार्डों में, आपरेशन थियेटरों में, इन्टेन्सिव केयर यूनिटों में जरूरी उपकरण, दवाएं ... या ... आक्सीजन सिलिण्डर हैं या नहीं। मेडिकल कालेज के डाक्टर की एक जरूरी व्यस्तता यह भी होती है कि कैसे प्रमोशन जल्दी-जल्दी मिले, हेड या प्रिंसिपल की कुर्सी कैसे मिले, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े – मंत्रियों का कृपापात्र बनने से लेकर दस्तावेजों में गोलमाल करने तक।

के.जी.एम.सी. लखनऊ में यही हुआ है। पैसे और पद की मारामारी में डाक्टर धीरे-धीरे इतने संवेदनहीन होते जाते हैं कि मरीजों का मरना-जीना उनके लिए एक रूटीनी बात बन जाती है। के.जी.एम.सी. के डाक्टर तर्क भी यही दे रहे हैं कि दो-चार बच्चों का मरना आम बात है। प्रशासनिक बदइन्तजामी के पीछे भी वही तर्क काम करता है जो डाक्टरों की लापरवाही और संवेदनहीनता के मामले में होता है।

इसलिए, यह बिल्कुल साफ है कि लखनऊ में शिशु संहार हुआ है – मुनाफे और बाज़ार की व्यवस्था के हाथों। इसलिए जब तक यह व्यवस्था नहीं खत्म होती, तब तक चिकित्सा के पेशे में गहरे जड़ जमा चुकी संवेदनहीनता को जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता। रोज-रोज की आम लापरवाहियों में न सही लेकिन ऐसी लोमहर्षक घटनाओं के समय असली हत्यारे हाथों की शिनाख्त करना ज़्यादा आसान होता है।

बेताल उवाच

विलासिता के टापू और ऐश्वर्य की मीनारें ध्वस्त होंगी राजन!

बेताल को कंधे पर लाद विक्रम चल पड़ा। अपनी आदत के अनुसार बेताल ने विक्रम से सवाल दागा –

"बोल राजन स्वर्ग कहां है और नर्क कहां?"

"स्वर्ग और नर्क तो परलोक में है। सद्कर्मों से स्वर्ग मिलता है और . .."

"फिर वही घिसा-पिता जवाब! परलोक किसने देखा? बता इस लोक में कहां है स्वर्ग और नर्क?"

"बेताल तू तो उल्टी खोपड़ी चलता है। भला इस लोक में भी स्वर्ग-नर्क हो सकता है? तू कहना क्या चाहता है?"

"राजन देख! एक मेरी दुनिया है जहां चलने को बस व रेल का किराया भी नहीं है। मेरे भाई आम की गुठली का जहरीला आटा खाकर जी रहे हैं – मर रहे हैं। मेरे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। और एक तेरी दुनिया है जहां दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध है, सुख-समृद्धि के, ऐशो आराम के सारे सामान मौजूद हैं। बता क्या यहां स्वर्ग-नर्क नहीं है?"

"कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहा है? यह तो दुनिया का दस्तूर है, पुराने कर्मों का फल है।"

"बहुत खूब! लुटेरों की तो एक ही भाषा है – पुराने कर्मों का फल है! जरा विचार तो कर अपने वैश्विक आकाओं की मायावी दुनिया पर। तेरे स्वर्ग-नर्क की परिभाषा आज बदल गयी है। जो दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा होगा, जितना बड़ा झूठा, मक्कार, फरेबी होगा, जनता का जितना अधिक खून चूसेगा वह स्वर्ग के उतने आलीशान आसन पर विराजमान होगा। उसके शौक भी उतने ही निराले और अनूठे होंगे।"

"तू क्या बक रहा है, बेताल!"

"मैं बक नहीं रहा सच्चाई बता रहा हूं। सच काफी कड़वा होता है राजन! अब तू ही बता, पिछले दिनों अमेरिकी करोड़पति डेनिस टीटो दो करोड़ डालर खर्च करके दुनिया का पहला अंतरिक्ष सैलानी बन बैठा। उसने आठ दिन अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 'इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन' में विश्राम किया। पिछले वर्ष तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके बिल गेट्स को पीछे ढकेलकर सबसे अमीर आदमी का दर्जा पाने वाला बदजुबान अमेरिकी अरबपति लैरी एलीसन अमेरिका में एक ऐसा जापानी महल बना रहा है जो जापानी सम्राटों को भी नसीब नहीं हुआ था। ब्राजील के साओ पाउलो शहर के अमीर अब छोटी-मोटी पार्टियों में भी अपनी कारों से नहीं हेलीकाप्टरों से जाना पसन्द करते हैं। मास्को के अमीर बाकायदा मोर्चों पर काम आने वाली बख्तरबंद गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। ... बता ये किसका स्वर्ग है? कितनों के पेटों पर लात मारकर मिल रहा है यह जन्नत का सुख। बोल राजन, बोल!"

"तू लोगों की खुशियों से जलने लगा है बेताल! यह तो दुनिया के विकास का प्रतीक है, परिणाम है। आज आदमी अंतरिक्ष में भी जाकर रह सकता है। दुनिया कितनी हसीन हो गयी है।"

"दुनिया हसीन बनी है मगर किसके लिए? अपने खून-पसीने से, अपनी मेहनत से दुनिया को खूबसूरत बनाने वाली भारी आबादी तो खुद दरिद्रता की ज़िन्दगी जी रही है। तेरी खूबसूरत दुनिया की हकीकत यह है कि मुनाफाखोर अमीरजादे और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और मेहनती ग़रीब आबादी की ज़िन्दगी और ज़्यादा बदहाल हो रही है। तेरी दुनिया में ऐसे-ऐसे सम्पत्तिवान हैं जिनमें से एक की पूंजी से भी कम में तीसरी दुनिया के कुछ ग़रीब मुल्कों की अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं।"

"राजन, तू सुन और बता कि समृद्धि की मीनारें कहां हैं। 1979 में अमेरिका की सबसे अमीर बीस प्रतिशत आबादी की औसत आय वहां की सबसे ग़रीब 20 प्रतिशत आबादी की तुलना में नौ गुनी थी। 1997 में औसत आय का यह अन्तर पंद्रह गुने का हो चुका था। अट्ठारह वर्षों के दौरान वहां की सबसे ग़रीब बीस प्रतिशत आबादी की आय में तीन प्रतिशत की और कमी हो गयी। अब अपने देश में ही देख। 1990-91 से 1998 के बीच ग़रीबों की संख्या में 11.5 करोड़ से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। देश के ऊपर की तीन फ़ीसदी आबादी और नीचे की 40 फीसदी आबादी की आमदनी के बीच का अन्तर 60 रुपये और एक रुपये का है। दुनिया में कुल 72 लाख ऐसे धनकुबेर हैं जो कहीं भी दस लाख डालर निवेश कर सकते हैं।"

"बोल नहीं राजन, पहले सुन, फिर दे जवाब। अपनी ही दुनिया के परोसे तथ्यों पर गौर कर। दुनिया के शीर्षस्थ अमीरज़ादों की सूची छापने वाली पत्रिका 'फोर्ब्स' ने 1982 में जब पहली सूची छापी थी तब अमीरों में सबसे निचली पायदान वाले व्यक्ति की सम्पदा नौ करोड़ डालर आंकी गयी थी। अट्ठारह वर्ष बाद सन 2000 में सबसे नीचे पांच सौवें स्थान पर आने वाले व्यक्ति की संपदा 72.5 करोड़ डालर अंकित है। सूची में तकरीबन तीन चौथाई धनपति डालरों में अरबपति थे। डालर अरबपतियों की संख्या जो पिछले साल 375 थी वो अब 425 हो गयी है। अब बता राजन, इन धनपशुओं की समृद्धि का राज क्या है? तू सच और इंसाफ की बड़ी-बड़ी बातें करता है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे।"

"तू जानना चाहता है तो सुन बेताल। अपनी मेहनत और दिमाग़ से उन्होंने धन कमाया है। वे जितना कमाते हैं उसका एक हिस्सा विज्ञान और तकनोलाजी के विकास पर खर्च करते हैं। नयी-नयी तकनीकें खोजते हैं, उससे समाज की उन्नति होती है, उससे उनकी भी कमाई में वृद्धि होती है।"

"झूठ, पक्का झूठ। ज्ञान-विज्ञान-तकनोलाजी का विकास उत्पादन से जुड़ा है। उत्पादन करती है आम मेहनती जनता और उस पर कुण्डली मारकर बैठे हैं धनपशु, समाज के जहरीले नाग। अपनी तिकड़मों और चालाकियों से इन्होंने पूरी ज्ञान-सम्पदा पर कब्जा कर रखा है। मुनाफे की अंधी हवस में पगलाये ये लुटेरे तो ज्ञान-विज्ञान के विकास के रास्ते के अब अवरोधक बन चुके हैं। ये हत्यारे हैं। मानव सभ्यता के विकास के मार्ग में रोड़ा हैं। वे पूरी ज्ञान सम्पत्ति का विकास अपने अंधे मुनाफे के लिए करते हैं और कर रहे हैं। इन्होंने उत्पादन के साधनों पर और पूरे राजकाज पर कब्जा कर रखा है ये कृत्रिम बाज़ार बनाते हैं और बाज़ार एवं मुनाफे के लिए उत्पादन करते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नहीं। वे पूरी दुनिया में ग़रीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, तबाही-बर्बादी पैदा करते हैं। वे बाज़ार की अंधी होड़ के लिए और अपनी मंदी से उबरने के लिए युद्ध की विनाशलीलाओं को जन्म देते हैं। उनकी समृद्धि की मीनारें और विलासिता के टापू करोड़ों मेहनतकश जनता की बर्बादी से खड़ा होता है।"

"तो तू क्या इसे रोक लेगा! इनके हाथ बहुत मजबूत हैं – लोहे के हैं, बेताल। हम सदियों से राज करते आये हैं, और भविष्य में भी करेंगे। तेरी जनता क्या कर लेगी।"

"तू इतिहास को भूल रहा है राजन। जनता जब-जब जागी है, संगठित हुई है तेरे जैसों की सत्ता को धूल में मिला दी है। तू अपनी चालाकियों से बार-बार भेष बदलकर "मानवीय" चेहरा बनाकर सत्ता पर काबिज हो जाता है। तू हर बार जनता को जाति-धर्म-क्षेत्र-नस्ल के नाम पर बांटने की कुत्सित साजिशें रचता है। लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। जनता एक बार फिर जाग रही है।"

"तेरी जनता तो भोली है, मूर्ख है। इसलिए दुर्दिन की शिकार है और रहेगी।"

"राजन, अब तू बहुत चिंघाड़ने लगा है। कहावत है कि 'जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है'। तेरी मौत अब सन्निकट है। जब इस 'भोली' और 'मूर्ख' जनता को तूफान उठेगा तो उसके ताप से तेरे लोहे के हाथ गल जाएंगे। तू इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जायेगा। इस बार तुझे और तेरे समूचे लुटेरे तंत्र को बंगाल की खाड़ी में इतने गहरे दफ़्न कर दिया जाएगा जहां से तू फिर कभी नहीं निकल पायेगा। तब उत्पादन, राजकाज और समाज के सम्पूर्ण ढांचे पर पैदा करने वालों का – मेहनतकश जनता का राज क़ायम होगा।"

इस पर विक्रम ने झुंझलाकर कहा, "बेताल तुम कैसी बहकी-बहकी और बेसिर-पैर की बातें कर रहे हो। तुम्हारे सवालों का जवाब देना बेकार का सिर खपाना है।"

"तुम्हारे पास मरी बातों का कोई जवाब नहीं है विक्रम" यह कहकर अट्टहास करते हुए बेताल अदृश्य हो गया।

–राम अवतार

मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी डा. दूधनाथ द्वारा 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ से प्रकाशित एवं उन्हीं के द्वारा वाणी ग्राफिक्स, अलीगंज, लखनऊ से मुद्रित। कम्पोजिंग : कम्प्यूटर प्रभाग, राहुल फाउण्डेशन, लखनऊ। संपादक मण्डल : डा. दूधनाथ, मुकुल। सम्पादकीय पता : 69, बाबा का पुरवा, पेपर मिल रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006, सम्पादकीय उपकार्यालय : जनगण होम्यो सेवासदन, मर्यादपुर, मऊ।